राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस
क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण शुक्रवार 17 जुलाई 2026 वर्ष-9,अंक-165 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम

आस्था का महासैलाब- बारिश में भी गूंजा जय जगन्नाथ

महाप्रभु के स्वागत में झूमे देश-विदेश के भक्त

भुवनेश्वर।

पूरे देश में आज आस्था और भक्ति का अनुपम नजारा देखने को मिल रहा है, जहाँ विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का भव्य शुभारंभ हो गया है। ओडिशा के पुरी स्थित श्री मंदिर में आयोजित होने वाली इस पावन यात्रा के दर्शन के लिए देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचे हैं। आज से शुरू हुई यह पावाना यात्रा 27 जुलाई को नीलाद्री बीजे के साथ संपन्न होगी। सुबह से ही भारी बारिश के बावजूद भक्तों का हौसला डगमगाया नहीं है। गीली सड़कों और बौछारों के बीच लाखों हाथ भगवान के विशाल रथों की पवित्र रस्सियों को थामने के लिए कतारों में मुस्तैद दिखे। शंखों की आवाज, घंटों की गूंज और जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। इस पावन अवसर पर प्रसिद्ध गायक सोनू निगम ने भी महाप्रभु के दर्शन किए। उन्होंने अभिभूत होकर कहा, मैंने पहले भी कई बार इसके लिए गाया है, लेकिन पहली बार साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। यहाँ मैंने जो कुछ भी देखा है, वह ज़िंदिगी भर मेरे साथ रहेगा। मुझे यहाँ का मैनेजमेंट बहुत पसंद आया। आस्था का यह रंग वैश्विक स्तर पर भी दिखा, जहाँ एक विदेशी भक्त ने भावुक होकर कहा, मैं भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करती हूँ कि वे हमारी सेवा स्वीकार करें। मैं अपने गुरु से प्रार्थना करती हूँ कि वे मुझे भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न करने की क्षमता दें; हम बस उनके दर्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। अनुष्ठानों के बीच सिंहद्वार पर सजे तीनों रथ पुरी मंदिर के सिंहद्वार पर महाप्रभु जगन्नाथ के नंदीघोष, भाई बलभद्र के तालध्वज और बहन सुभद्रा के दर्पदलन रथ को पूरी भव्यता के साथ खड़ा किया गया है। रथयात्रा से पहले वैदिक मंत्रोच्चार और हवन-यज्ञ के बीच तीनों रथों की विधिवत प्रतिष्ठा संपन्न की गई। इस दौरान सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए नंदीघोष पर श्रीहनुमान, तालध्वज पर श्रीनृसिंह और देवदलन रथ पर मां भुवनेश्वरी की स्थापना की गई। रथ यात्रा के दौरान ओडिशी नृत्यांगनाओं का मनमोहक नृत्य एक प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा के रूप में जीवंत हो उठा, जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और ओडिशा की समृद्ध विरासत का प्रतीक है। धार्मिक अनुष्ठान के बाद तीनों विग्रह अलग-अलग रथों पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। मान्यता है कि रथ की रस्सी खींचने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए हर कोई इसके लिए बेताब नजर आ रहा है।

यात्रा से ठीक पहले केंद्रीय मंत्रियों और स्थानीय मंत्रियों ने पुरी के गोवर्धन पीठ का दौरा कर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया।

सोने की झाड़ू से पहिंद कर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रवाना की भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथयात्रा

- विकसित भारत के संकल्प में गुजरात रहेगा सबसे आगे, भगवान से राज्य की खुशहाली और समृद्धि का मांगा आशीर्वाद

अहमदाबाद

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को आषाढ़ी दूज के पावन अवसर पर अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं रथयात्रा को प्रस्थान कराने से पूर्व मंदिर परिसर में भगवान जगन्नाथ जी और उनके रथ की पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लगातार पांचवीं बार भगवान जगन्नाथ जी के रथ की सोने की झाड़ू से सफाई कर पहिंद विधि संपन्न की। इसके बाद मुख्यमंत्री भगवान के मुख्य रथ को नगर यात्रा के लिए मंदिर परिसर से भक्ति-भावपूर्वक बाहर लाने में सहभागी हुए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी इस रस्म में भक्ति-भावपूर्वक सहभागी हुए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रथयात्रा के इस पर्व पर सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने इसे अपना सौभाग्य माना कि उन्हें आषाढ़ी दूज के पावन अवसर पर भगवान के दर्शन, आरती और रथयात्रा को प्रस्थान कराने का अवसर मिला। मुख्यमंत्री ने भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं रथयात्रा के अवसर पर राज्य के सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान जगन्नाथ जी आज भाई बलराम और बहन सुभद्रा जी के साथ नगर यात्रा पर निकले हैं। प्रभु आज स्वयं चलकर श्रमिकों, गरीबों और सभी नागरिकों को आशीर्वाद और दर्शन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वासपूर्वक कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, इस संकल्प को पूरा करने के लिए गुजरात सबसे आगे रहेगा।

वांगचुक का अनशन- केंद्र सरकार पर बढ़ा दबाव, अमेरिका से अपील

नई दिल्ली।

पर्यावरणविद् और शिक्षाविद सोनम वांगचुक का दिल्ली के जंतर-मंतर पर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में कथित अनियमितताओं और शैक्षिक सुधारों की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन जारी है। उनका स्वास्थ्य दिन-ब-दिन बिगड़ता जा रहा है, जिस पर अब देश और विदेश से गहरी चिंता व्यक्त की जा रही है। देशभर से उनसे अनशन तोड़ने की अपीलें हो रही हैं।इस कड़ी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी भारतीय प्रवासी समूह, द हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स ने एक खुला पत्र लिखकर वांगचुक से बातचीत करने और उनका अनशन तुड़वाने की अपील की है।

पुरी रथयात्रा में बारिश भी नहीं रोक सकी आस्था,लाखों श्रद्धालुओं ने किए भगवान जगन्नाथ के दर्शन

ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा को लेकर भक्तों में अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। रथयात्रा के दिन पुरी में रुक-रुक कर बारिश जारी रही, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। भारी बारिश के बावजूद लाखों की संख्या में भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन के लिए एकत्रित हुए। भक्तों का कहना है कि भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा में बारिश कोई बाधा नहीं है, बल्कि यह प्रभु का आशीर्वाद है। उनका कहना है कि रथयात्रा के दौरान बारिश होना कोई नई बात नहीं है और वे पहले से ही इसके लिए तैयार रहते हैं। भक्तों के लिए सबसे बड़ा उत्साह भगवान के दर्शन करना और रथ खींचने के पवित्र अवसर का हिस्सा बनना है। श्री जगन्नाथ मंदिर के चुनरा सेवायत शरत मोहंती ने बताया कि मंदिर के अंदर सभी महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि मंदिर की सभी नीतियां इतनी जल्दी पूरी हुई हों। उनके अनुसार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्वयं भगवान जगन्नाथ की इच्छा है कि वे जल्द से जल्द मंदिर से बाहर निकलकर लाखों भक्तों को रथ पर विराजमान होकर दर्शन दें। उन्होंने बताया कि मंगला आरती के बाद भगवान की स्नान पूजा और अन्य विधियां संपन्न हुईं। इसके बाद भगवान का श्रृंगार और विशेष वेश धारण कराया गया। फिर गोपाल वल्लभ भोग और सकाल धूप यानी राजभोग के रूप में खिचड़ी भोग अर्पित किया जाएगा। इसके बाद भगवान को मंगला अर्पण कर रथारोहण की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने बताया कि इसके बाद पाहांडी बिजे की परंपरा निभाई जाएगी, जिसमें भगवान के विग्रहों को क्रम से मंदिर से बाहर लाया जाता है। सबसे पहले चक्रराज सुदर्शन, फिर भगवान बलभद्र, माता सुभद्रा और अंत में भगवान जगन्नाथ रथ पर

विराजमान होंगे। शरत मोहंती ने कहा कि बारिश के बावजूद लाखों भक्त बड़दांड में भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही भगवान बाहर आएंगे, घंटों, मृदंग और अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठेगा।

भारत और फिनलैंड यूरोपीय संघ के एफटीए के तहत अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए तैयार हैं- पीयूष गोयल

नई दिल्ली ।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को फिनलैंड की उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री रिक्का पुर्रा से मुलाकात कर दोनों देशों के बीच आर्थिक और वित्तीय सहयोग को मजबूत बनाने, व्यापार और निवेश बढ़ाने तथा डिजिटलीकरण और उभरते क्षेत्रों में साझेदारी का विस्तार करने पर चर्चा की।

बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) के तहत भारत और फिनलैंड के बीच सहयोग को और गहरा करने की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया।

पीयूष गोयल बेल्जियम और स्पेन की सफल यात्रा के बाद फिनलैंड पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने फिनलैंड के आर्थिक मामलों के मंत्री साकारी पुइस्तो के साथ भी महत्वपूर्ण बैठक की।

गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरएंडडी), स्टार्टअप और बिजनेस पार्टनरशिप को मजबूत बनाने के उपायों पर सार्थक चर्चा हुई।

उन्होंने बताया कि बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), 6जी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेमिकंडक्टर, स्पेस और सस्टेनेबिलिटी जैसे भविष्य के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार किया गया। साथ ही इस बात पर भी चर्चा हुई कि भारत-ईयू एफटीए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को किस तरह नई गति दे सकता है।

फिनलैंड यात्रा का मुख्य उद्देश्य इनोवेशन, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल रिसर्च जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करना है।

यात्रा के दौरान पीयूष गोयल फिनलैंड की प्रमुख कंपनियों के साथ आयोजित इंडिया-फिनलैंड बिजनेस राउंडटेबल में भी हिस्सा लेने वाले हैं। इस बैठक में डिजिटलीकरण, क्लीन एनर्जी, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और

सर्कुलर इकोनॉमी से जुड़ी फिनलैंड की कंपनियां शामिल होंगी।

इसके अलावा, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और बिजनेस फिनलैंड के बीच संस्थागत सहयोग को मजबूत बनाने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे।

पीयूष गोयल फिनलैंड की कई प्रमुख कंपनियों और इनोवेशन संस्थानों, जिनमें नोकिया कॉरपोरेशन, वीटीटी रिसर्च सेंटर, कोने कॉरपोरेशन और केम्पी ग्रुप शामिल हैं, का भी दौरा करेंगे। इस दौरान टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, 6जी रिसर्च, स्मार्ट मोबिलिटी, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल मशीनरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल मोबिलिटी, इंडस्ट्रियल इनोवेशन और निवेश के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा होगी।

यह यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने तथा भारत-ईयू एफटीए को जल्द लागू करने की दिशा में दोनों पक्ष सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।

जेल से बाहर आएगी सिया गोयल? शादी का सबूत ढूंढ रही पुलिस

पुणे।

अदालत के आदेश पर केतन अग्रवाल हत्याकांड की मुख्य आरोपी सिया गोयल की न्यायिक हिरासत आज समाप्त हो रही है। उसके प्रेमी चेतन चौधरी को भी उसी मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। यदि अदालत आज उनकी हिरासत की अवधि नहीं बढ़ाती है, तो दोनों आज जेल से बाहर आ सकते हैं, हालांकि इसकी संभावना काफी कम है। इस बीच, पुणे पुलिस की एक टीम राजस्थान पहुंच गई है, जहां वे चेतन और सिया गोयल की कथित गुप्त शादी के सबूत ढूंढने की कोशिश कर रही है, जो इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।

इससे पहले जांच अधिकारियों ने अदालत से दोनों आरोपियों से आगे पूछताछ के लिए तीन दिनों की पुलिस कस्टडी की मांग की थी। पुलिस ने यह दलील दी थी कि मामले की गहराई तक पहुंचने के लिए दोनों आरोपियों को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ करना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही, अदालत को यह भी बताया गया था कि इस मामले से जुड़े कई चैट्स और अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत अभी बरामद किए जाने और उनकी गहन जांच होना बाकी है। हालांकि, कोर्ट ने पुलिस की इस मांग को खारिज करते हुए दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था, जिससे पुलिस की जांच कुछ समय के लिए धीमी पड़ गई।

इससे पहले, अदालत ने पुलिस को आरोपियों की सात दिनों की कस्टडी दी थी, जिसे बाद में जांच के 18 प्रमुख पहलुओं पर पूछताछ के लिए चार दिन और बढ़ा दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप, आरोपी सिया और चेतन से पुलिस पहले ही कुल 11 दिनों तक हिरासत में रखकर गहन पूछताछ कर चुकी है। केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच कर रही पुणे ग्रामीण पुलिस की क्राइम ब्रांच अब राजस्थान में है। जांच के दौरान पुलिस को यह अहम जानकारी मिली थी कि सिया गोयल और उसका प्रेमी चेतन चौधरी पिछले साल दिसंबर में राजस्थान गए थे।

श्रीकृष्ण पांच वक्त की नमाज पढ़ते थे वाले बयान पर बवाल

दावा- भगवान श्रीकृष्ण मुस्लिम थे और पांच वक्त की नमाज पढ़ते थे

वायरल वीडियो पर हिंदू संगठनों का विरोध, पुलिस में शिकायत धर्मगुरुओं ने भी जताई कड़ी आपत्ति

इटावा ।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद के बीच इटावा के मौलाना जरजिश अंसारी का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में मौलाना द्वारा भगवान श्रीकृष्ण को लेकर की गई टिप्पणियों पर हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की है।

बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो 23 जून का है, जिसमें मौलाना झारखंड में आयोजित एक धार्मिक सभा को संबोधित करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में वह कथित तौर पर दावा करते हैं कि भगवान श्रीकृष्ण मुस्लिम थे और पांच वक्त की नमाज पढ़ते थे। उन्होंने अपने दावे के समर्थन में श्रीमद्भगवद्गीता के एक श्लोक का उल्लेख करते हुए उसकी अपनी व्याख्या प्रस्तुत की।

हालांकि, धार्मिक विद्वानों का कहना है कि भगवद्गीता के जिस श्लोक का हवाला दिया गया है, उसमें इस्लाम या नमाज का कोई उल्लेख नहीं है। उनका कहना है कि श्लोक का संबंध योग, आत्मसंयम और ईश्वर साधना से है, न कि किसी विशेष धार्मिक परंपरा से।

वीडियो वायरल होने के बाद कई हिंदू संगठनों ने इसे करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताते हुए मौलाना के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अयोध्या के कुछ

संतों और धर्मगुरुओं ने भी इस बयान पर नाराजगी जताई और इसे ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत बताया।

इस बीच अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में मौलाना के खिलाफ शिकायत दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन हजरतगंज थाने और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगा। फिलहाल मामले को लेकर सोशल मीडिया पर बहस जारी है। प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या कानूनी कार्रवाई की पुष्टि नहीं की गई है।

स्वर्ण कांता शर्मा हटी, लेकिन केजरीवाल और सहयोगियों ने नहीं दिया जवाब

हाई कोर्ट ने दिया आखिरी मौका

नई दिल्ली ।

कथित दिल्ली आबकारी नीति मामले में विशेष अदालत द्वारा बरी होने के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया है। दिल्ली की अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप नेता दुर्गेश पाठक को अपना पक्ष रखने के लिए एक और, पर अंतिम मौका दिया है। पूर्व में जब जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मामले की सुनवाई कर रही थीं, तब आप के नेताओं ने सुनवाई का बहिष्कार किया था।

हालांकि, अब बेंच बदलकर जस्टिस मनोज जैन के पास आने के बाद भी प्रतिवादियों की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया।

गगनयान और चंद्रयान-3 से जुड़े 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने छोड़ी नौकरी

नई दिल्ली ।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के गगनयान और चंद्रयान-3 जैसे अत्यंत महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण मिशनों से जुड़े वैज्ञानिकों के इस्तीफों ने अंतरिक्ष विभाग की चिंता काफी बढ़ा दी है। पिछले कुछ महीनों के भीतर 100 से अधिक वैज्ञानिकों द्वारा नौकरी छोड़ने के बाद, विभाग ने इस पलायन को रोकने के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 14 जुलाई को जारी एक नए आंतरिक मेमोरेंडम के जरिए वैज्ञानिकों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) और इस्तीफे के नियमों को पहले से कहीं अधिक सख्त कर दिया गया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब इसरो अपने सबसे बड़े मिशनों को अंजाम देने में जुटा है।

इस्तीफा देने वालों में कई बड़े और अहम प्रोजेक्ट्स से जुड़े अधिकारी भी शामिल हैं, जो इस समस्या की गंभीरता को और बढ़ा देता है। वीएसएससी से एलवीएम-3 (लॉन्च व्हीकल मार्क-3) के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विक्टर जोसेफ ने इस्तीफा दे दिया है। इसी तरह, यूआरएससी से स्पैडेक्स प्रोजेक्ट के डायरेक्टर ने भी नौकरी छोड़ दी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चंद्रयान-3 जैसे ऐतिहासिक मिशन का हिस्सा रहे आदित्य रालापल्ली ने भी इस्तीफा दिया है। वह मिशन के प्रोजेक्ट मैनेजर (सिमुलेशन) थे, और उनकी टीम ने चंद्रमा पर लैंडिंग को सत्यापित करने के लिए 1 लाख से अधिक परीक्षण किए थे, जिससे लगभग 25 टेराबाइट डेटा तैयार हुआ था। इस्तीफों की इस लगातार बढ़ती हुई श्रृंखला को देखते हुए, प्रशासन ने 2020 में बनाए गए नियमों को रद्द कर दिया है। पहले इसरो के सेंटर डायरेक्टर्स को ग्रुप ए के तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मियों के इस्तीफे और वीआरएस को सीधे मंजूरी देने का अधिकार था। लेकिन नए आदेश के बाद, गगनयान और अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मिशनों से जुड़े वैज्ञानिकों के इस्तीफे अब सेंटर डायरेक्टर एक सामान्य प्रक्रिया के तहत मंजूर नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे सभी मामलों को डायरेक्टर की सिफारिश के साथ अंतिम निर्णय के लिए सीधे अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) को भेजना अनिवार्य होगा। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि किसी भी महत्वपूर्ण परियोजना पर अचानक कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। रिपोर्ट के अनुसार, इसरो के चेयरमैन वी. नारायणन ने इस्तीफों की बात को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा, यह सच है कि कई लोग जा रहे हैं,

लेकिन यह हर संगठन का एक सामान्य हिस्सा है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि नया मेमोरेंडम केवल लोगों को रोकने के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है कि अचानक से कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट प्रभावित न हो। उन्होंने विश्वास जताया कि अगर कोई जाता है, तो कोई दूसरा उसकी जिम्मेदारी संभालेगा और इसरो पूरी स्थिति को संभालने में सक्षम है। इसरो में वर्तमान में 14,600 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

महंगाई की नई मार : आरबीआई के लक्ष्य से ऊपर पहुंची खुदरा महंगाई आम आदमी का बजट बिगड़ा खाद्य वस्तुओं और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने बढ़ाई चिंता

महंगाई बढ़ने का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के लिए नया आधार वर्ष और नई उपभोक्ता टोकरी लागू होने के बाद यह महंगाई का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। नई उपभोक्ता टोकरी में लोगों की वर्तमान जीवनशैली और खर्च के पैटर्न को अधिक वास्तविक रूप से शामिल किया गया है। इससे महंगाई का आकलन पहले की तुलना में अधिक सटीक माना जा रहा है। हालांकि इससे यह भी स्पष्ट हुआ है कि लोगों के दैनिक खर्च में वास्तविक बढ़ोतरी पहले के अनुमान से अधिक है।

(लेखक – कांतिलाल मांडोत)

देश में महंगाई ने एक बार फिर आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जून महीने में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.38 प्रतिशत पर पहुंच गई है। पिछले 17 महीनों में यह पहला अवसर है जब महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 4 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य से ऊपर पहुंची है। इससे पहले मई में खुदरा महंगाई 3.95 प्रतिशत दर्ज की गई थी। महंगाई में यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार हुई वृद्धि का परिणाम मानी जा रही है। इसके साथ ही परिवहन लागत बढ़ने से रोजमर्रा की जरूरत का लगभग हर सामान महंगा हो गया है, जिसका सीधा असर आम परिवारों के मासिक बजट पर दिखाई देने लगा है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में खाद्य महंगाई बढ़कर 5.32 प्रतिशत पर पहुंच गई, जबकि मई में यह 4.78 प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य महंगाई 5.45 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 5.09 प्रतिशत दर्ज की गई। यह स्पष्ट संकेत है कि गांव और शहर दोनों ही महंगाई की मार झेल रहे हैं। फल, सब्जियां, दालें, खाद्य तेल, दूध तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी ने रसोई का खर्च काफी बढ़ा दिया है। मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए घर का बजट संभालना पहले की तुलना में अधिक कठिन हो गया है।

महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हुई वृद्धि भी रही है। ईंधन महंगा होने से माल ढुलाई की लागत बढ़ गई है। ट्रांसपोर्ट महंगा होने का असर केवल परिवहन क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव हर उस वस्तु पर पड़ता है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। किराना, फल-सब्जियां, दवाइयां, कपड़े, निर्माण सामग्री और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें भी परिवहन खर्च बढ़ने के कारण ऊपर चली जाती हैं। जून महीने में माल ढुलाई से जुड़ी सेवाओं की महंगाई दर बढ़कर लगभग 7.70 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो यह बताती है कि परिवहन लागत अब महंगाई का बड़ा कारण बन चुकी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बनी अनिश्चितता ने भी ईंधन की कीमतों पर दबाव बढ़ाया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा प्रभाव भारत जैसे आयात पर निर्भर देश पर पड़ता है। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। ऐसे में वैश्विक परिस्थितियां बिगड़ने पर घरेलू बाजार में भी पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाते हैं। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का असर अब सीधे आम नागरिक की जेब पर महसूस किया जा रहा है।

महंगाई बढ़ने का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के लिए नया आधार वर्ष और नई उपभोक्ता टोकरी लागू होने के बाद यह महंगाई का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। नई उपभोक्ता टोकरी में लोगों की वर्तमान जीवनशैली और खर्च के पैटर्न को अधिक वास्तविक रूप से शामिल किया गया है। इससे महंगाई का आकलन पहले की तुलना में अधिक सटीक माना जा रहा है। हालांकि इससे यह भी स्पष्ट हुआ है कि लोगों के दैनिक खर्च में वास्तविक बढ़ोतरी पहले के अनुमान से अधिक है।

महंगाई का सबसे अधिक असर निश्चित आय वाले परिवारों पर पड़ता है। जिन लोगों की आय सीमित है या जिनकी आय में नियमित वृद्धि नहीं होती, उनके लिए बढ़ती कीमतों के बीच खर्चों का संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। वेतनभोगी कर्मचारी, छोटे व्यापारी, किसान, मजदूर और पेंशनभोगी सभी इस स्थिति से प्रभावित हो रहे हैं। आवश्यक वस्तुओं पर अधिक खर्च होने के कारण लोग अन्य जरूरतों पर खर्च कम करने को मजबूर हो रहे हैं। इससे उपभोक्ता मांग पर भी असर पड़ सकता है, जो अर्थव्यवस्था की गति को प्रभावित करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख उद्देश्य महंगाई को नियंत्रित रखते हुए आर्थिक विकास को संतुलित बनाए रखना है। आरबीआई ने खुदरा महंगाई के लिए 4 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया है और 2 से 6 प्रतिशत के दायरे को स्वीकार्य सीमा माना गया है। हालांकि जून में महंगाई लक्ष्य से ऊपर पहुंच गई है, लेकिन यह अभी भी आरबीआई की निर्धारित ऊपरी सीमा 6 प्रतिशत से नीचे है। इसके बावजूद लगातार बढ़ती महंगाई केंद्रीय बैंक के लिए चिंता का विषय बन सकती है। यदि आने वाले महीनों में महंगाई का दबाव बना रहता है तो ब्याज दरों को लेकर आरबीआई को अधिक सतर्क रुख अपनाना पड़ सकता है।

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि यदि खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण नहीं पाया गया और कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रहीं तो आने वाले महीनों में महंगाई और बढ़ सकती है। दूसरी ओर यदि मानसून सामान्य रहता है, कृषि उत्पादन अच्छा होता है और सरकार समय रहते आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने के कदम उठाती है तो खाद्य महंगाई में कुछ राहत मिल सकती है। अच्छी फसल से सब्जियों, अनाज और दालों की कीमतों में स्थिरता आने की संभावना रहती है।

सरकार के सामने फिलहाल दोहरी चुनौती है। एक ओर उसे महंगाई पर नियंत्रण रखना है तो दूसरी ओर आर्थिक विकास की गति भी बनाए रखनी है। इसके लिए खाद्य आपूर्ति को मजबूत करना, जमाखोरी पर सख्ती, परिवहन व्यवस्था को सुचारु रखना और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी होगा। यदि आपूर्ति श्रृंखला मजबूत रहती है तो कीमतों पर नियंत्रण पाने में मदद मिल सकती है।

आर्थिक जानकारों का मानना है कि महंगाई केवल आंकड़ों का विषय नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध आम नागरिक के जीवन स्तर से है। जब खाद्य पदार्थ, ईंधन और दैनिक उपयोग की वस्तुएं महंगी होती हैं तो परिवारों की बचत कम होने लगती है। उपभोक्ता खर्च घटता है और इसका प्रभाव पूरे आर्थिक तंत्र पर दिखाई देता है। इसलिए महंगाई पर नियंत्रण केवल सरकार या आरबीआई की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उत्पादन, आपूर्ति और बाजार व्यवस्था के बेहतर समन्वय से ही संभव है।

जून महीने के महंगाई के आंकड़े यह संकेत देते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था फिलहाल नई चुनौती का सामना कर रही है। पिछले 17 महीनों में पहली बार आरबीआई का लक्ष्य टूटना यह बताता है कि कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है। यदि आने वाले महीनों में खाद्य वस्तुओं और ईंधन की कीमतों पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ऐसे समय में सरकार, रिजर्व बैंक और संबंधित एजेंसियों को समन्वित प्रयास करते हुए महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण के उपाय करने होंगे, ताकि आम नागरिक को राहत मिल सके और अर्थव्यवस्था संतुलित विकास की दिशा में आगे बढ़ती रहे।

(वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार-स्तम्भकार)

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संपादकीय

सुनें तार्किक विरोध

भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती रही है कि यहां हर अलग राय व असहमति को सम्मान मिला है। निश्चय ही यह दृष्टि लोकतंत्र को मजबूत ही करती है। जब हम कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो प्रतिरोध की आवाज को सुनने के लिये नीति-नियंताओं को बड़ा दिल भी दिखाना चाहिए। एक बार फिर इस भावना की परीक्षा तब हो रही है, जब हमारे देश में लाखों बच्चों का भविष्य तय करने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठे हैं। परीक्षा प्रणाली की शुचिता बनाये रखने के लिये शिक्षाविद् और इनोवेटर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल एक अहम मोड़ पर पहुंच गई है। उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर देश में चिंता है। उनका वजन काफी कम हुआ है, रक्त शर्करा कम हुई है और कमजोरी आने की बात कही जा रही है। निश्चित रूप से राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से हटकर उनकी खराब होती सेहत हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। निश्चय ही वांगचुक किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते और न ही वे यह आंदोलन किसी निजी लाभ के लिये कर रहे हैं। वे भले ही छात्रों के भविष्य के मुद्दे को लेकर अस्तित्व में आई- 'कॉकरोच जनता पार्टी' के समर्थन में खड़े हुए हों, लेकिन उनकी चिंता के केंद्र में उन लाखों छात्रों का भविष्य है, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के तौर-तरीकों को लेकर अविश्वास जता रहे हैं। उनके आंदोलन के मूल में उन लाखों अभिभावकों की फिक्र है, जिनका भरोसा बार-बार पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रियाओं में अनियमितताओं को लेकर डगमगा रहा है। कहना मुश्किल है कि लगाया जा रहा हर आरोप सही ही हो, लेकिन एक बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि देश की कई महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं में लोगों का विश्वास कम हुआ है। ऐसे में देश के नीति-नियंताओं को पारदर्शी सुधार लाकर और बेहतर जवाबदेही के माध्यम से दरके हुए विश्वास को जल्द बहाल करने की जरूरत है। निर्विवाद रूप से ये लोकतंत्र का तकाजा भी है कि सत्ताधीशों को किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन नागरिकों की बात को भी सुनना चाहिए, जो नीतियों की विसंगतियों को लेकर सवाल उठा रहे हों। यह जानते हुए कि उनकी राजनीतिक दल विशेष से कोई प्रतिबद्धता नहीं है। निस्संदेह, देश में कोई भी सरकार जनता के अभिभावक के रूप में होती है। वैसे भी किसी शांतिपूर्ण विरोध की लंबे समय तक अनदेखी से आंदोलनकारियों और आम लोगों में सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ता है। निस्संदेह, यदि आंदोलनकारियों से बातचीत की पहल होती है तो इसको उसकी कमजोरी नहीं कहा जाएगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भूख हड़ताल के नैतिक और चिकित्सीय पहलू भी होते हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह आंदोलन कर रहे व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करते हुए उसके जीवन की रक्षा करे। वहीं दूसरी ओर किसी भी चिकित्सीय हस्तक्षेप के दौरान कानून और चिकित्सा-संबंधी नैतिक नियमों का पालन किया जाना भी जरूरी है। इस बात में दो राय नहीं है कि मौजूदा गतिरोध से किसी का भी भला नहीं हो सकता। सही मायने में बातचीत की शुरुआत करने के लिये सरकार को हर मांग को पूरा करने की जरूरत भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर आंदोलनकारियों को भी बातचीत को सार्थक बनाने के लिये प्रयासरत रहने की जरूरत है। ऐसे में समस्या के समाधान के लिये एक भरोसेमंद समिति और चिंताओं से जुड़े मुद्दों पर विचार करने के लिये एक तय समय-सीमा वाला रोडमैप, भरोसे की कमी को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है। सही मायने में इस आंदोलन के मानवीय पक्ष पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। यानी सरकार समझने की कोशिश करे कि इस आंदोलन के जन्म लेने के पीछे क्या भावनाएं काम कर रही थीं।

मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (MPMS): आत्मनिर्भर भारत से वैश्विक प्रौद्योगिकी नेतृत्व की ओर एक निर्णायक कदम

(लेखक-विनोद कुमार सिंह 'तकियावाला')

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम(MPMS) को मंजूरी दिया जाना भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक और दूरगामी महत्व का निर्णय है। 62,500 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान वाली यह योजना केवल मोबाइल फोन निर्माण बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, अनुसंधान, डिज़ाइन और नवाचार का अग्रणी केंद्र बनाना है।यह योजना ऐसे समय में लाई गई है, जब बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए लागू उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI-LSEM) 31 मार्च 2026 को समाप्त हो चुकी है। नई योजना उस सफलता को अगले चरण तक ले जाने का प्रयास है। इसका कार्यकाल वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पाँच वर्षों का होगा।एमपीएमएस के अंतर्गत भारत में निर्मित मोबाइल फोन की पात्र बिक्री पर 2.25 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। यदि निर्माता प्रमुख पुर्जों और उप-असेंबलियों की घरेलू खरीद बढ़ाते हैं तो उन्हें 1.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं भारतीय ब्रांडों को डिज़ाइन, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के लिए 3 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इससे स्पष्ट है कि सरकार केवल असेंबली आधारित उत्पादन नहीं, बल्कि वास्तविक तकनीकी क्षमता, नवाचार और बौद्धिक संपदा निर्माण को प्रोत्साहित करना चाहती है।सरकार का अनुमान है कि योजना की अवधि में देश में लगभग 39 लाख करोड़ रुपये मूल्य के मोबाइल फोन का संचयी उत्पादन होगा। साथ ही मोबाइल फोन निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा लगभग 60,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर इससे कहीं अधिक होंगे, जिससे लाखों युवाओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं और महिलाओं को रोजगार मिलने की संभावना है।पिछले एक दशक में 'मेक इन इंडिया' अभियान के तहत भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2014-15 की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन लगभग सात गुना तथा निर्यात ग्यारह गुना बढ़ चुका है। आज भारत मात्रा के आधार पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है और देश में उपयोग होने वाले 99.2 प्रतिशत मोबाइल फोन भारत में ही निर्मित हो रहे हैं।वर्ष 2025 में स्मार्टफोन भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद बन गया, जिसने डीजल ईंधन और कटे-तराशे हीरों जैसे पारंपरिक निर्यात उत्पादों को भी पीछे छोड़ दिया। यह उपलब्धि दर्शाती है कि भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखला में अपनी स्थिति लगातार मजबूत कर रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र अब भारतीय अर्थव्यवस्था की नई विकास धुरी बनता जा रहा है।नई योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें भारतीय कंपनियों को अपने स्वयं के ब्रांड, डिज़ाइन और अनुसंधान विकसित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया गया है।लंबे समय तक भारत वैश्विक कंपनियों के लिए विनिर्माण केंद्र बना रहा, लेकिन अब लक्ष्य केवल निर्माण नहीं, बल्कि तकनीकी स्वावलंबन, भारतीय पेटेंट और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय ब्रांड तैयार करना है।घरेलू मूल्य संवर्धन बढ़ाने पर विशेष बल देने से मोबाइल फोन उद्योग में चिप,कैमरा मॉड्यूल, डिस्प्ले,बैटरी,प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और अन्य महत्वपूर्ण पुर्जों के निर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे आयात पर निर्भरता घटेगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और आपूर्ति श्रृंखला अधिक मजबूत तथा सुरक्षित बनेगी।आज वैश्विक कंपनियाँ अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने की दिशा में तेजी से काम कर रही हैं।ऐसे समय में भारत के पास कुशल मानव संसाधन,विशाल घरेलू बाजार,बेहतर अवसंरचना और अपेक्षाकृत स्थिर नीतिगत वातावरण जैसी महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। एमपीएमएस इन सभी क्षमताओं को एकीकृत करते हुए भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है।हालाँकि इस योजना की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि घरेलू अनुसंधान एवं विकास, सेमीकंडक्टर निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट उद्योग, कौशल विकास और नवाचार को समान गति से आगे बढ़ाया जाए। यदि इन क्षेत्रों में भी निरंतर और लक्षित निवेश हुआ तो भारत केवल मोबाइल फोन का निर्माण ही नहीं करेगा, बल्कि भविष्य की मोबाइल तकनीकों के विकास और निर्यात में भी अग्रणी भूमिका निभा सकेगा।स्पष्ट है कि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम केवल एक प्रोत्साहन योजना नहीं,बल्कि भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर, नवाचार-आधारित और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स महाशक्ति बनाने की दीर्घकालिक रणनीति का महत्वपूर्ण आधार है।आने वाले वर्षों में यह योजना भारतीय उद्योग,रोजगार,निर्यात और तकनीकी नेतृत्व को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। यदि इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ, तो यह पहल भारत को केवल दुनिया का बड़ा बाजार ही नहीं, बल्कि दुनिया का विश्वसनीय तकनीकी निर्माता और नवाचार केंद्र भी बना सकती है।

प्रयत्न में ऊब नहीं

संसार में गति के जो नियम हैं, परमात्मा में गति के ठीक उनसे उलटे नियम काम आते हैं और यहीं बड़ी मुश्किल हो जाती है।

संसार में ऊबना बाद में आता है, प्रयत्न में ऊब नहीं आती। इसलिए संसार में लोग गति करते चले जाते हैं। पर परमात्मा में प्रयत्न में ऊब आती है और प्रयत्न पहले ही उबा देगा, तो आप रुक जाएंगे। कितने लोग हैं जो प्रभु की यात्रा शुरू भर करते हैं, पर कभी पूरी नहीं कर पाते। कितनी बार तय किया कि स्मरण कर लेंगे प्रभु का घड़ीभर! एकाध दिन, दो दिन। फिर ऊब गए। फिर छूट गया। कितने संकल्प, कितने निर्णय, धूल होकर पड़े हैं चारों तरफ! लोग कहते हैं कि ध्यान से कुछ हो सकेगा? मैं कहता हूं जरूर हो सकेगा। कठिनाई सिर्फ एक है, सातत्य! कितने दिन कर सकोगे? मुश्किल से कोई मिलता है, जो तीन महीने भी सतत कर पाता है। दस-पांच दिन बाद ऊब जाता है! आश्चर्य है कि मनुष्य जिंदगी भर अखबार पढ़कर नहीं ऊबता, रेडियो सुनकर नहीं ऊबता, फिल्म देखकर नहीं ऊबता, रोज वही बातें करके नहीं ऊबता। ध्यान करके क्यों ऊब जाता है? आखिर ध्यान में ऐसी क्या कठिनाई है! कठिनाई एक ही है कि संसार की यात्रा पर प्रयत्न नहीं उबाता, प्राप्ति उबाती है और परमात्मा की यात्रा पर प्रयत्न उबाता है, प्राप्ति कभी नहीं उबाती। जो पा लेता है, वह फिर कभी नहीं ऊबता। बुद्ध ज्ञान के बाद चालीस साल जिंदा थे। चालीस साल किसी ने एक बार उन्हें अपने ज्ञान से ऊबते हुए नहीं देखा। कोहनूर हीरा मिल जाता 2369?भूति खोकर गृह-कलह के बीज बो दिए। शक्ति के सहारे सत्ता का संचालन होता तो न रावण मारा जाता और न कौरवों को पराजय का मुंह देखना पड़ता। पिछली सदी तक भारत का शासन-सूत्र अंग्रेज संभाल रहे थे, शक्ति की उनके पास कमी नहीं थी। उनके सामने भारत छोड़ने की विवशता शक्ति की कमी से नहीं थी। ये प्रसंग प्रमाणित करते हैं कि प्रबुद्ध जनता केवल शक्ति के आधार पर शासित नहीं हो सकती।

विचार मंथन

दो पाटों के बीच फंसा भारत?

(लेखक- सनत जैन)

अमेरिका और इजरायल के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए अन्य देशों के साथ दूरियां बढ़ाकर संबंधो को सतही बना लिया। भारत और चीन के बीच का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। भारत का निर्यात कम होता जा रहा है, भारत का आयात बढ़ता चला जा रहा है।

भारत पिछले कुछ वर्षों से आंख बंद करके अमेरिका और इजरायल के पक्ष में खड़ा हुआ है। अमेरिका और इजरायल के कारण भारत की, दुनिया के अन्य देशों के साथ दूरियां बढ़ती जा रही है। अमेरिका और इजरायल ने भारत का भरपूर लाभ लिया। किसी भी मौके पर भारत का वैसा साथ नहीं दिया, जैसा भारत ने अमेरिका और इजराइल का व्यापारिक, सामरिक एवं आर्थिक मामलों में साथ दिया है। हाल ही में अमेरिका एक नया प्रस्ताव लेकर आ रहा है। जिसमें रूस से तेल खरीदी करने पर 100 फ़ीसदी टैरिफ भारत पर लगाने का प्रस्ताव है। पहले अमेरिका ने भारत को धमकाने के लिए 500 फ़ीसदी टैरिफ लगाने की बात कही गई। इसके पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ को लेकर भारी दबाव बनाया। अमेरिका के दबाव में भारत ने रूस और ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। जिसके कारण भारत को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा अन्य मामलों में भी अमेरिका ने जिस तरह से भारत के ऊपर दबाव बनाया। ऑपरेशन सिंदूर पर दबाव डालकर सीज फायर कराया। रूस-यूक्रेन युद्ध में रुस से तेल आयात कर यूरोपीय देशों को निर्यात कराने में अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका थी। उसी को आधार बनाकर अब भारत के ऊपर टैरिफ लगाने जैसी कार्रवाई पर यही कहा जा सकता है। भारत अंतरराष्ट्रीय संबंधों और कूटनीतिज्ञ संबंधो में महाशक्तियों के बीच फंसकर रह गया है। भारत सरकार ने तात्कालिक व्यापारिक लाभ को देखते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को महत्ता दी। अमेरिका और इजरायल के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए अन्य देशों के साथ दूरियां बढ़ाकर संबंधो को सतही बना लिया। भारत और चीन के बीच का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। भारत का निर्यात कम होता जा रहा है, भारत का आयात बढ़ता चला जा रहा है। चीन और पाकिस्तान के साथ हमारे सीमा संबंधी विवाद हैं। पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिश्ते चीन के दबाव में अच्छे नहीं हैं। भारत के पड़ोसी देशों को चीन एक-एक करके अपने पाले में ले रहा है। ईरान से भारत कच्चा तेल आयात करता था, बदले में भारत से वस्तुओं का आयात और रुपए में ट्रांजैक्शन करता था। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका के दबाव में भारत ने संबंध एक तरह से दुनिया के अन्य देशों के साथ बहुत सतही बना लिए हैं। 140 करोड़ की आबादी वाला देश जिसकी क्रय शक्ति दुनिया में सबसे ज्यादा है। ऐसे समय में भारत दुनिया के देशों के साथ बराबरी के साथ कारोबार एवं संबंधों को बेहतर नहीं कर पा रहा है। चीन और इजरायल की गोद में बैठकर भारत की दुनिया के देशों से दूरियां बन गई हैं। भारत की यह स्थिति सबसे खराब है। कहा जाता है, दो पाटों के बीच अनाज कभी साबूत नहीं रह सकता है। कुछ इसी तरह की स्थिति वैश्विक व्यापारिक एवं सामरिक संबंधों को लेकर भारत की हो रही है। एक तरफ चीन-रूस का दबाव, ईरान के साथ भारत के रिश्ते दांव पर लगे हुए हैं। पिछले 4 महीने से अमेरिका और ईरान के युद्ध में ईरान का पलड़ा भारी होता जा रहा है। कच्चे तेल, गैस और खाद के लिये हम खाड़ी के देशों पर निर्भर है। इसके बाद भी अमेरिका, भारत के ऊपर लगातार दबाव बना रहा है। समझ नहीं आ रहा है, भारत का कौन सच्चा दोस्त है। मुसीबत पडने पर कौन भारत के साथ खड़ा रहेगा। अभी जो स्थिति दिख रही है, भारत को सभी देशों का दबाव झेलना पड़ रहा है। यह स्थिति स्वतंत्रता के बाद पहली बार देखने को मिल रही है। गुटनिरपेक्ष देशों के रूप में जब हम आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे। तब भी हमारी यह हालत नहीं थी, जो आज है। भारत सरकार को अपनी विदेशी नीति और व्यापारिक संबंधो के साथ-साथ सामरिक दृष्टि से रक्षा नीति पर भारत सरकार को गंभीरता के साथ ध्यान देने की जरूरत है। समय पर सही निर्णय नहीं ले पाने से भारत को भविष्य में भारी नुकसान होना तय है।

विंडफॉल टैक्स में 7 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी

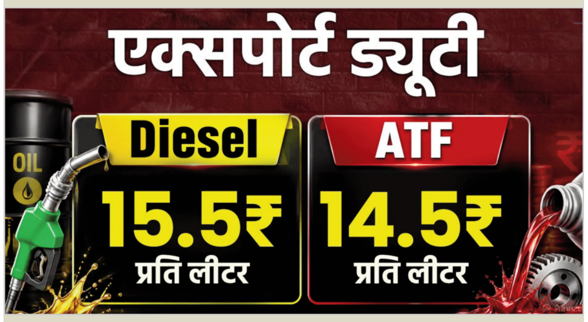

नई दिल्ली।

अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के मद्देनजर भारत ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में 7 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात शुल्क में कमी कर थोड़ी राहत दी गई है। नई दरें 16 जुलाई से प्रभावी हो गई हैं। सरकारी आदेश के अनुसार, डीजल पर निर्यात शुल्क 8.5 रुपए से बढ़ाकर 15.5 रुपए प्रति लीटर और एटीएफ पर 7.5 रुपए से बढ़ाकर 14.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी को 4 रुपए से घटाकर 2.5 रुपए प्रति लीटर किया गया है। यह फैसला पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने, ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी और ईरान के जवाबी हमलों के कारण लिया गया है। इन घटनाओं से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल आपूर्ति बाधित होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं, जिससे ब्रेंट क्रूड की कीमतें उछलकर 84.7 रुपए प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं। रूस से कम निर्यात और ईंधन बाजार में तंगी जैसी वजहों से डीजल रिफाइनिंग मार्जिन में हुई बढ़ोतरी भी इस कदम का एक कारण है।

महंगाई की आशंका से गिरे सोने-चांदी के दाम

- घरेलू बाजार में सोना 540 और चांदी 924 रुपए तक लुढ़की

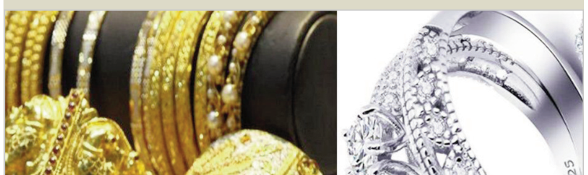

नई दिल्ली।

सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। गुरुवार 16 जुलाई को घरेलू बाजार (एमसीएक्स) में सोना और चांदी दोनों ही दबाव में कारोबार करते दिखे। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका और ईरान-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है, जिससे महंगाई के ऊंचे बने रहने का डर सता रहा है। इसका सीधा असर पीली और सफेद धातु की कीमतों पर दिख रहा है। कीमतों में तेज गिरावट घरेलू वायदा बाजार (एमसीएक्स) पर सोने का भाव 540 रुपये प्रति 10 ग्राम गिर गया है। वहीं चांदी के दाम में भी 924 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद एमसीएक्स पर सोना 1,41,310 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने पर दबाव देखा गया, जबकि चांदी में हल्की तेजी रही, हालांकि कुल मिलाकर बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। गिरावट के प्रमुख कारण सोने-चांदी की कीमतों में इस गिरावट के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव प्रमुख कारण है, जिससे कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और महंगाई का जोखिम फिर से बढ़ गया है। पहले, अमेरिका में थोक और खुदरा महंगाई के आंकड़े नरम रहने से फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी न करने की उम्मीद जगी थी, लेकिन अब भू-राजनीतिक तनाव ने परिदृश्य बदल दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर महंगाई ऊंची बनी रहती है, तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लंबे समय तक उच्च स्तर पर बनाए रख सकता है।,

पेटीएम देगा निवेशकों को बोनस शेयर का तोहफा

रिकॉर्ड मुनाफे के बाद बोर्ड बैठक में होगा फैसला

नई दिल्ली।

डिजिटल भुगतान मंच पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने अपने निवेशकों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। कंपनी पहली बार बोनस शेयर जारी करने की योजना बना रही है, जो वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 552 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज करने और भुगतान तथा वित्तीय सेवा कारोबार में अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के बाद उठाया गया कदम है। कंपनी ने शेयर बाजारों को दी सूचना में बताया कि उसका निदेशक मंडल 20 जुलाई को होने वाली बैठक में 30 जून को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों के साथ बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर विचार करेगा। आवश्यक मंजूरियों के अधीन, निदेशक मंडल उसी बैठक में बोनस शेयर का अनुपात और रिकॉर्ड तिथि भी तय करेगा। यह निर्णय वित्त वर्ष 2025-26 में 552 करोड़ रुपये के उल्लेखनीय शुद्ध लाभ के बाद आया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में उसे 663 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। बोनस शेयर मौजूदा शेयरधारकों को उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में अतिरिक्त शेयर प्रदान करते हैं, जिससे कंपनी अपनी वित्तीय मजबूती और दीर्घकालिक वृद्धि की संभावनाओं पर भरोसा जताती है। यह कदम खुदरा निवेशकों के लिए शेयर को अधिक सुलभ बनाने और लिक्विडिटी बढ़ाने में भी मदद करेगा।

रुपया गिरावट पर बंद

मुंबई।

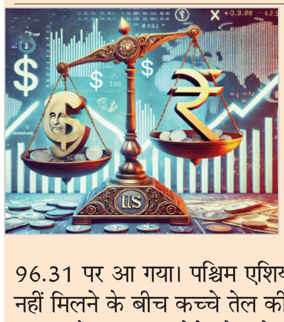

भारतीय रुपया गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 0.1फीसदी कमजोर होकर 96.3450 पर बंद हुआ। वहीं पिछले सत्र में यह 96.2550 पर बंद हुआ था। आज सुबह शुरुआती कारोबार में रुपया छह पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 96.31 पर आ गया। पश्चिम एशिया संकट के कम होने के कोई संकेत नहीं मिलने के बीच कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव और डॉलर के मजबूत होने से घरेलू मुद्रा पर दबाव है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि विदेशी पूंजी की निकासी से स्थानीय मुद्रा पर दबाव बना रहा। हालांकि, घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक शुरुआत से रुपये को कुछ समर्थन मिला। वहीं अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 96.28 प्रति डॉलर पर खुला। फिर फिसलकर 96.31 प्रति डॉलर पर आ गया जो पिछले बंद भाव से छह पैसे की गिरावट दिखाता है। स्थानीय मुद्रा बुधवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले नौ पैसे कमजोर होकर 96.25 पर बंद हुई थी।

इंडिया सिरोस ईवी को कर सकती है भारत में लॉन्च

नई दिल्ली।

भारतीय बाजार में किआ इंडिया अपने इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए तैयार है, और जल्द ही सिरोस ईवी को लॉन्च करने की योजना बना रही है। यह किआ की भारत में सबसे छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी, जो कैरेंस क्लैविस ईवी से नीचे रखी जाएगी। इसका सीधा मुकाबला टाटा नेक्सन ईवी, मारुति ई-विटारा और महिंद्रा एक्सयूवी 400 जैसे मॉडलों से होगा। किआ सिरोस ईवी को 42 किलोवॉट-घंटा और 51.4 किलोवॉट-घंटा बैटरी पैक विकल्पों के साथ पेश किया जा सकता है। यह बैटरी क्षमता हुंडई किआक्रेटा ईवी और किआ कैरेंस क्लाविस ईवी के समान है, लेकिन सिरोस के छोटी और हल्की होने के कारण इससे बेहतर ड्राइविंग रेंज मिलने की उम्मीद है। 42 किलोवॉट-घंटा बैटरी के साथ लगभग 443 किलोमीटर और 51.4 किलोवॉट-घंटा बैटरी के साथ लगभग 520 किलोमीटर तक की रेंज का दावा किया जा सकता है, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी में से एक बना देगा। सबसे खास बात यह है कि कंपनी इस गाड़ी के साथ इंडस्ट्री की सबसे अच्छी 15 साल या लाइफटाइम बैटरी वारंटी दे सकती है, जो भारत में उपलब्ध सबसे व्यापक बैटरी कवरेज प्लान में से एक होगा। इसके साथ 3 साल की स्टैंडर्ड गाड़ी वारंटी भी मिलेगी, ।

सेबी ने जून में 5,000 से अधिक निवेशक शिकायतें निपटाईं, लंबित मामलों में कमी

नई शिकायतें भी तेजी से सुलझीं; पुरानी 17 शिकायतें अभी भी तीन माह से अधिक समय से लंबित

नई दिल्ली।

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने जून महीने में अपनी ऑनलाइन शिकायत वारण प्रणाली स्कोर्स के जरिए 5,000 से अधिक निवेशक शिकायतों का निपटारा किया है, जो प्रभावी शिकायत समाधान की दिशा में एक मजबूत प्रतिबद्धता दर्शाता है। इस अवधि में नई शिकायतें भी तेजी से सुलझाई गईं, जिससे लंबित मामलों की संख्या में कमी आई है। सेबी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून में स्कोर्स पर 5,035 नई शिकायतें दर्ज की गईं, जबकि 5,037 शिकायतों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। इसके परिणामस्वरूप 30 जून को लंबित शिकायतों की संख्या घटकर 5,524 रह गई, जो पहले 5,537 थी। नियामक ने बताया कि शिकायतों पर संबंधित इकाइयों ने कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करने में औसतन चार दिन और प्रथम स्तर की समीक्षा वाली शिकायतों के निस्तारण में औसतन आठ दिन का समय लिया, जो मंच की दक्षता को दर्शाता है। हालांकि, जून के अंत तक 17 शिकायतें तीन महीने से अधिक समय से लंबित थीं, जिनमें आदित्य बिड़ला मनी लिमिटेड, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज और एचबीएल पावर सिस्टम्स जैसी प्रमुख इकाइयों से संबंधित मामले शामिल हैं। सेबी ने स्पष्ट किया कि लंबित शिकायतों में वे भी शामिल हो सकती हैं जहाँ एटीआर जमा हो चुका है, लेकिन निवेशक अभी भी जवाब से असंतुष्ट होने पर समीक्षा का अनुरोध कर सकते हैं। स्कोर्स 2.0 के तहत, शिकायतें स्वतः संबंधित इकाई को भेजी जाती हैं और निवेशक को 21 दिनों में कार्रवाई रिपोर्ट मिलती है। असंतुष्टि

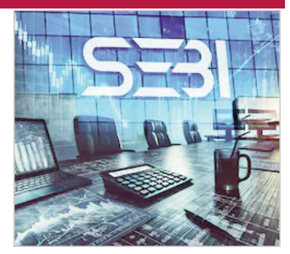

की स्थिति में, निवेशक 15 दिन के भीतर प्रथम और फिर द्वितीय स्तर की समीक्षा का अनुरोध कर सकते हैं,

जहाँ सेबी स्वयं जांच करता है, जिससे निवेशकों को न्याय सुनिश्चित होता है।

रूसी तेल खरीद पर 100 फीसदी शुल्क का प्रस्ताव

संशोधित मसौदे में भारत सहित रूस के 5 सबसे बड़े ऊर्जा खरीदार निशाने पर

नई दिल्ली।

अमेरिका में दोनों दलों के सीनेटरों के एक समूह ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक का एक संशोधित मसौदा पेश किया है, जिसमें रूस के कच्चे तेल और गैस के पांच सबसे बड़े खरीदारों पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। इस सूची में भारत भी शामिल है, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूसी तेल पर बढ़ती निर्भरता के कारण एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना कर सकता है। यह संशोधित विधेयक पिछले मसौदे से भिन्न है, जिसे पहले सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने प्रस्तावित किया था, जिसमें रूस से ऊर्जा के सभी संभावित खरीदारों पर 500 प्रतिशत शुल्क लगाने का प्रस्ताव था। नए मसौदे में भारत, चीन, हंगरी, स्लोवाकिया और अजरबैजान जैसे शीर्ष पांच खरीदारों को विशेष रूप से लक्षित किया गया है, जबकि ज्यादातर यूरोपीय देशों को इससे बाहर रखा गया है। भारत के लिए यह विधेयक ऐसे समय में आया है जब वह पश्चिम एशिया से आपूर्ति बाधाओं और रूसी तेल पर मिल रही भारी छूट के कारण जून में रूस से अपने कच्चे तेल का आयात बढ़ाकर 25.8 लाख बैरल प्रति दिन कर चुका है। मैरीटाइम इंटेलिजेंस फर्म केप्लर के आंकड़ों के अनुसार, जून में भारत के कुल कच्चे तेल के आयात में रूस का योगदान लगभग 50 प्रतिशत रहा। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण आपूर्ति बाधित होने की आशंका के चलते जुलाई में भी रूसी तेल की खरीद मजबूत रहने की उम्मीद है। यह विधेयक भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों को भी जटिल कर सकता है। एक सरकारी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि व्यापार वार्ता में इस विधेयक पर अभी तक चर्चा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि व्यापार समझौते में शुल्क संबंधी चिंताओं के साथ-साथ इस विधेयक के प्रभाव पर भी बात होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अपनी ऊर्जा नीति को राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा पर आधारित रखना जारी रखना चाहिए, क्योंकि अमेरिकी सीनेट में पारित होने के बावजूद इस विधेयक के लागू होने की संभावना कम है। उन्होंने सलाह दी कि भारत को चीन की तरह रूसी तेल खरीदना जारी रखना चाहिए। केप्लर के लीड रिसर्च एनालिस्ट सुमित रितोलिया ने भी स्वीकार किया कि भारत के लिए रूसी कच्चे तेल के समान पैमाने, विश्वसनीयता और किफायती विकल्प खोजना मुश्किल होगा। इस पृष्ठभूमि में, 15 जुलाई को ब्रेंट क्रूड की कीमतें एक सप्ताह पहले के 75 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 85 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। हालांकि, राष्ट्रपति को अमेरिकी राष्ट्रीय हित में प्रतिबंध हटाने का अधिकार भी है।

पीएफ खातों में अब न्यूनतम शेष राशि अनिवार्य

अंतिम निपटान में कम राशि को देखते हुए लाया गया नियम

नई दिल्ली (ईएमएस)। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सदस्यों की सेवानिवृत्ति बचत बढ़ाने के उद्देश्य से कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026 के तहत भविष्य निधि (पीएफ) खातों में न्यूनतम शेष राशि अनिवार्य कर दी है। यह कदम तब उठाया गया है जब संगठन के लगभग आधे (48.7 फीसदी) सदस्यों के खाते में अंतिम निपटान के समय मात्र 10,000 से 20,000 रुपये ही रहते हैं, जो उनकी सेवानिवृत्ति के लिए पर्याप्त नहीं होते। ईपीएफओ ने बताया कि इस नए नियम से सेवानिवृत्ति के परिणामों में काफी सुधार की उम्मीद है, जिससे लगभग आधे सदस्यों की बुढ़ापे की बचत में 35 गुना तक की बढ़ोतरी हो सकती है। नई योजना बीमारी, शिक्षा, शादी और घर जैसे खास मकसद वाली निकासी के लिए एक समान प्रारूप लाती है, जिसकी अनुमति 12 महीने की सेवा पूरी करने के बाद मिलेगी। हालांकि, अब सदस्यों को आंशिक निकासी के बाद भी खाते में एक अनिवार्य न्यूनतम शेष बनाए रखना होगा। ईपीएफओ के अनुसार, जहां पहले 15,000 रुपये प्रति माह कमाने वाला कर्मचारी 20 साल में 14 लाख तक जमा कर सकता था, वहीं अब 75 प्रतिशत राशि निकालने के बाद भी उसके खाते में लगभग 3.5 लाख रुपये की न्यूनतम शेष राशि बनी रहेगी।

बंधुआ मजदूरी पर भारत की अधिसूचना, अमेरिकी शुल्क में राहत की आस

सरकार ने बंधुआ मजदूरी से निर्मित सामान के आयात पर लगाई रोक

नई दिल्ली।

भारत ने बंधुआ मजदूरी से बने उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि इससे अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर प्रस्तावित धारा 301 के तहत लगाए जाने वाले शुल्क में कुछ नरमी आने की उम्मीद है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूएसटीआर) ने पिछले महीने भारत सहित कई देशों पर बंधुआ मजदूरी से जुड़े आयात की जांच के बाद 12.5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क का प्रस्ताव किया था। वहीं पाकिस्तान, इंडोनेशिया और मैक्सिको जैसे देशों को बंधुआ मजदूरी से निर्मित वस्तुओं के आयात रोकने हेतु 'आंशिक व्यवस्था' लागू करने के कारण 10 प्रतिशत का कम शुल्क प्रस्तावित था। भारत सरकार ने इस सप्ताह बंधुआ मजदूरी का उपयोग करके निर्मित वस्तुओं के आयात को रोकने के लिए अधिसूचना जारी की है। वाणिज्य एवं उद्योग महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी इस अधिसूचना में बंधुआ मजदूरी को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की परिभाषा के अनुरूप परिभाषित किया गया है। यह कदम भारत को उसी अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप लाता है जिसका उपयोग अमेरिका घरेलू स्तर पर करता है। ऐसे में भारत को अब यूएसटीआर की जांच पर अंतिम रिपोर्ट में, जो संभवतः इस महीने जारी होगी, भारतीय सामानों के लिए बेहतर शुल्क परिणाम की उम्मीद है। अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 301 अमेरिका को उन व्यापार प्रथाओं की जांच करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति देती है।

जिन्हें वह अपने कारोबार के लिए हानिकारक मानता है। भारत और अमेरिका व्यापार समझौते के लिए भी बातचीत कर रहे हैं, जिसमें इन मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है।

आरबीआई ने वित्तीय संस्थानों के लिए डेटा जोखिम प्रबंधन मसौदा जारी किया

बैंकों, एनबीएफसी को मजबूत करनी होगी डेटा गवर्नेंस व्यवस्था

नई दिल्ली।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) सहित अपने नियामक दायरे में आने वाली संस्थाओं के लिए डेटा से संबंधित जोखिमों के प्रबंधन हेतु एक मसौदा मानक जारी किया। केंद्रीय बैंक का लक्ष्य वित्तीय संस्थानों में आंकड़ों की बढ़ती मात्रा और विविधता के बीच उनकी सटीकता, निरंतरता, सुरक्षा और उपयोगिता सुनिश्चित करना है। मसौदे में आंकड़ों के रखरखाव, भूमिकाओं, गुणवत्ता, साझाकरण और तीसरे पक्ष की व्यवस्था से जुड़े मानकों पर विशेष जोर दिया गया है। ये दिशानिर्देश अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) फ्रेमवर्क के 1 अप्रैल, 2027 से लागू होने से पहले आए हैं, जिसके लिए बैंकों से अपने आंकड़ा संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की अपेक्षा की गई है। आरबीआई ने कहा कि आंकड़ों की मात्रा और गति बढ़ने से प्रभावी डेटा गवर्नेंस व्यवस्था अनिवार्य हो गई है। प्रस्तावों के अनुसार बैंकों और एनबीएफसी को एक कार्यकारी-स्तरीय डेटा गवर्नेंस समिति का गठन करना होगा या मौजूदा समिति को यह जिम्मेदारी सौंपनी होगी। निदेशक मंडल को समग्र डेटा गवर्नेंस रूपरेखा की निगरानी करनी होगी और संबंधित रिपोर्टों की समीक्षा करनी होगी।

छोटी एसआईपी में निवेशकों की धूम, पर बनाए रखना बड़ी चुनौती

सेबी की पहल से छोटे निवेशकों को बढ़ावा, पर बाजार की अस्थिरता उच्च बंदी दर

नई दिल्ली।

कम रकम वाली सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी), खासकर 250 रुपये के निवेश विकल्प वाली छोटी एसआईपी, भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। हालांकि, इनमें निवेश बंद होने की दर भी काफी अधिक बनी हुई है, जो पहली बार निवेश करने वाले लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करती है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के आंकड़ों के अनुसार, जून 2026 तक छोटी एसआईपी की कुल संख्या 3.22 लाख हो गई, जो अप्रैल 2025 में 1.97 लाख थी। यह वृद्धि सेबी द्वारा फरवरी 2025 में 250 रुपये की एसआईपी योजना शुरू करने के बाद हुई है, जिसका उद्देश्य छोटे निवेशकों को प्रोत्साहित करना था। हालांकि, इस श्रेणी में निवेश बंद होने की दर भी चिंताजनक है। मई 2026 में 26,000 से अधिक एसआईपी बंद हो गईं। सितंबर 2025 से प्रति माह औसतन 28,000 नई एसआईपी शुरू हुईं, जबकि 20,000 एसआईपी बंद होती रहीं। उद्योग जगत के विशेषज्ञों और एम्फी के अनुसार पहली बार निवेश करने वाले अक्सर बाजार में उतार-चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

म्युचुअल फंडों ने जून में रणनीतिक सौदों से बढ़ाई इक्विटी खरीद

नई दिल्ली।

जून माह में म्युचुअल फंडों ने इक्विटी बाजार में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए ब्लॉक डील, पात्र संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) और ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) जैसे नियोजित लेनदेन का व्यापक उपयोग किया। म्युचुअल फंडों ने इन रणनीतिक सौदों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण हिस्सेदारी बनाने के लिए किया। जून में सबसे ज्यादा खरीदे गए शीर्ष 10 शेयरों में अदाणी एंटरप्राइजेज (ब्लॉक डील), जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर (क्यूआईपी), एक्मे सोलर होल्डिंग्स (क्यूआईपी) और एनएचपीसी (ओएफएस) प्रमुख रहे। अदाणी एंटरप्राइजेज में एक बड़ी ब्लॉक डील हुई, जबकि जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर और एक्मे सोलर होल्डिंग्स ने क्यूआईपी के जरिए पूंजी जुटाई, वहीं सरकार ने ओएफएस के जरिए एनएचपीसी में हिस्सेदारी बेची। लेंसकार्ट सॉल्यूशंस और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस में भी पिछले महीने बड़ी ब्लॉक डील हुई थीं और ये भी जून में सबसे ज्यादा खरीदे गए 15 अग्रणी शेयरों में शामिल रहे। इन नियोजित लेनदेन वाले शेयरों के अलावा, म्युचुअल फंडों ने बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा, मीशो, कोल इंडिया और इटर्नल जैसे शेयरों में भी महत्वपूर्ण निवेश किया। पिछले महीने, शीर्ष 10 खरीदे गए शेयरों में म्युचुअल फंडों से कुल मिलाकर 32,000 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश आया।

सेबी ने बोर्ड सदस्यों के लिए सख्त की आचार संहिता, हितों के टकराव पर रोक

नए नियमों में डिस्क्लोजर, अनाधिकृत निवेश पर कड़ा शिकंजा

नई दिल्ली।

बाजार नियामक सेबी ने अपने बोर्ड सदस्यों के लिए प्रशासनिक ढांचे में बदलाव किए हैं। पारदर्शिता बढ़ाने और हितों के टकराव को रोकने के उद्देश्य से नियामक ने नई आचार संहिता जारी की है, जिसमें डिस्क्लोजर, खुद को कार्यवाही से अलग करने (रिक्यूजल) और अनाधिकृत निवेशों से जुड़े नियमों को काफी सख्त किया गया है। यह नई संहिता 2008 की 5 पेज की पिछली संहिता की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है (17 पेज)। यह व्यापक नैतिक दिशानिर्देशों के बजाय नियमों के पालन पर अधिक जोर देती है। इसके तहत, पूर्णकालिक सदस्य और उनके परिवार वाले अपने कार्यकाल के दौरान उन योजनाओं में नया निवेश नहीं कर सकेंगे जिनकी इजाजतनहीं है। मौजूदा अनाधिकृत होल्डिंग की जानकारी देना भी अनिवार्य होगा। नई संहिता ऐसे अनाधिकृत निवेशों को संभालने के विकल्प भी बताती है ।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

बेल्जियम के अनुभवी मिडफील्डर टिलेमैन्स मैनचेस्टर यूनाइटेड से खेलते नजर आयेंगे

लंदन ।

बेल्जियम के अनुभवी मिडफील्डर यूरी टिलेमैन्स अब इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के एक प्रमुख क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड की ओर खेलते हुए दिखेंगे। मैनचेस्टर ने मिडफील्डर यूरी के साथ जून 2031 तक के लिए करार किया है। यह ट्रांसफर सभी जरूरी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आधिकारिक रूप से लागू किया जाएगा। वह 2026/27 सीजन से पहले माइकल कैरिक की टीम से जुड़ेंगे और नंबर 18 की जर्सी पहनेंगे। ये जर्सी क्लब के महान मिडफील्डर पॉल स्कोल्स ने 1996/97 सीजन से लेकर 2010/11 तक पहनी थी।

टिलेमैन्स ने बेल्जियम की ओर से 90 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और हाल ही में फीफा विश्व कप में बेल्जियम के क्वार्टर फाइनल तक के सफर में इनकी अहम भूमिका रही है। वहीं स्कोल्स जैसे दिग्गज की नंबर 18 की जर्सी पहनना उनके लिए सम्मान की बात होगी।

2027 एकदिवसीय विश्व कप में तीन बार होगा भारत-पाकिस्तान का मुकाबला

मुम्बई ।

भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मुकाबलों का इंतजार हमेशा से ही क्रिकेट प्रशंसकों को रहता है। इसका कारण ये है कि इस मुकाबले में बेहद रोमांच रहता है। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण राजनीतिक संबंधों के कारण इनके बीच से द्विपक्षीय सीरीज बंद हैं, ऐसे में प्रशंसकों को इन दोनो की टक्कर केवल आईसीसी टूर्नामेंटों में देखने को मिलती है। ऐसे में प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर है। साल 2027 में होने वाले एकदिवसीय विश्वकप में उन्हें तीन बार भारत-पाक मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। इसका कारण है कि आईसीसी ने अपनी बैठक में टूर्नामेंट के प्रारुप में जो बदलाव किये हैं उससे इन दोनो टीमों के बीच अधिक से अधिक मुकाबलो की राह बन गयी है। आईसीसी ने साल 2027 विश्वकप के लिए टीमों की संख्या बढ़ाकर 14 करने का फैसला लिया है। आईसीसी ने नए और कमजोर एसोसिएट देशों के लिए ऐसी बाधाएं लगा दी हैं कि मुख्य दौर तक पहुंचते-पहुंचते केवल बड़ी टीमों का ही दबदबा रहेगा। नियमों के अनुसार, रैंकिंग में सबसे नीचे की तीन टीमों के बीच एक त्रिकोणीय सीरीज खेली जाएगी जिसमें से केवल एक ही आगे बढ़ पाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि व्यावहारिक रूप से टूर्नामेंट में खेलने वाली टीमों की संख्या 14 से घटकर केवल 12 ही रह जाएगी। इसके अलाव इन 12 टीमों के बीच पहले राउंड के मुकाबले होने के बाद, केवल 7 टीमें ही अगले दौर में पहुंचेंगी, जिसे 'सुपर सेवन' का नाम दिया गया है। यानी दो कड़े क्वालिफिकेशन राउंड्स पार करने के बाद

केवल 7 मुख्य टीमों को ही आपस में खेलने का असली मौका मिलेगा। एक रिपोर्टों के अनुसार, इस कठिन प्रारुप को रखने कका कारण भारत और पाकिस्तान के बीच ज्यादा से ज्यादा मुकाबले कराना है, क्योंकि यह मुकाबला आईसीसी के लिए भारी कमाई और ब्रॉडकास्टर्स के लिए लाभ का सबसे बड़ा जरिया होता है। नये प्रारुप के तहत ही भारत और पाकिस्तान को एक ही छह-टीमों वाले ग्रुप में रखा जाएगा, जहां उनके बीच टूर्नामेंट का पहला मुकाबला होगा। दोनों टीमों के मजबूत प्रदर्शन को देखते हुए उनका सुपर सेवन में पहुंचना तकरीब तय है।

सिंधु जीत के साथ ही जापान ओपन के क्वार्टर फाइनल पहुंची

टोक्यो ।

भारत की महिला बैडमिटन स्टार पीवी सिंधु जीत के साथ ही जापान ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गयी हैं। सिंधु ने महिला एकल मुकाबले में चीन की विश्व की नंबर 5 खिलाड़ी हान यू को सीधे गेमों में 21-16, 21-14 से हराया। विश्व रैकिंग में 10 वीं वरीयता प्राप्त सिंधु मुकाबले में पूरे समय विरोधी खिलाड़ी पर हावी रहीं। इस जीत के साथ ही सिंधु अपनी जीत की लय बनाये रखी है और वह लगातार बेहतर होती जा रही हैं।

पहले गेम में सिंधु ने धीमी शुरुआत की पर जल्द ही उन्होंने अपनी लय हासिल करते हुए बढ़त दर्ज की। वहीं दूसरे गेम में भी वह हावी रहीं और उन्होंने 8-0 की बढ़त हासिल करते विरोधी खिलाड़ी हान यू को वापसी का कोई अवसर नहीं दिया। नहीं चीनी खिलाड़ी ने वापसी के प्रयास किये पर असफल रही। इस जीत के साथ ही सिंधु ने हान यू के खिलाफ अपना जीत हार का रिकॉर्ड 8-1 कर लिया है, जिससे पता चलता है कि वह मैच में हावी रही हैं। अब

बीएफडब्ल्यू सुपर 750 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में शुक्रवार को सिंधु का मुकाबला जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोज़ोमी ओकुहारा से होगा। ओकुहारा को उनके दूसरे राउंड के मैच से दक्षिण कोरिया की टॉप सीड एन से-यंग के हटने के कारण वॉकओवर मिला और वे सीधे अगले दौर में पहुंच गईं।वहीं एक अन्य मुकाबले में भारत की मिश्रित युगल जोड़ी ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो प्री-क्वार्टर फाइनल में हार के साथ ही बाहर हो गयी है। ध्रुव और तनीषा को चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी फेंग यान झे और हुआंग डोंग पिंग के हाथों 47 में 22-20, 21-17 से हार का सामना करना पड़ा है।

14 अगस्त से होगा यूपी टी-20 लीग का आगाज,कानपुर करेगा प्लेऑफ और फाइनल मैच की मेजबानी

लखनऊ।

यूपी टी-20 लीग के चौथे सीजन का आगाज 14 अगस्त से होगा। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला काशी रुद्रास और मौजूदा चैंपियन मेरठ मावेरिक्स के बीच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह टूर्नामेंट 24 दिनों तक चलेगा और इसका फाइनल मैच 6 सितंबर को कानपुर में होगा। लीग के इतिहास में पहली बार टूर्नामेंट दो स्थानों पर खेला जाएगा। टूर्नामेंट का शुरुआती चरण लखनऊ में होगा, जहां इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 13 दिनों में 22 मैच खेले जाएंगे। इसके बाद टूर्नामेंट का दूसरा हिस्सा कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में होगा, जहां बाकी 12 मैच खेले जाएंगे। शेड्यूल की घोषणा पर यूपी टी20 लीग की गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन संजय कपूर ने कहा, ÷यूपी टी20 लीग हर सीजन के साथ आगे बढ़ रही है, और इस साल एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि टूर्नामेंट पहली बार दो जगहों पर खेला जाएगा। शुरुआती चरण लखनऊ में होगा और उसके बाद दूसरा चरण और प्लेऑफ के मुकाबले कानपुर में खेले जाएंगे।÷ ÷पिछले कुछ सालों में क्रिकेट का स्तर बहुत बेहतर हुआ है, और हमें भरोसा है कि यह सीजन एक बार फिर प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों को अनुभवी खिलाड़ियों के साथ अपनी काबिलियत दिखाने का शानदार मंच देगा। हम सभी टीमों को सीजन के लिए शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि फैंस यूपी टी20 लीग के एक और रोमांचक सीजन का आनंद लेंगे।÷ ओपनिंग सेरेमनी और सीजन का पहला मैच लखनऊ में होगा।

आईसीसी ने एकदिवसीय और टी20 विश्वकप के नये प्रारुप को मंजूर किया

एडिनबर्ग।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने खेल का रोमांच बढ़ाने के लिए एकदिवसीय और टी20 विश्वकप के नये प्रारुप को मंजूरी दे दी है। इससे इन टूर्नामेंटों में भाग लेने वाली टीमों को लाभ होगा बल्कि खेल का रोमांच भी बढ़ेगा। आईसी ने कहा कि इस बदलाव से विश्वकप और टी20 विश्कवप का महत्व और भी बढ़ जाएगा। आईसीसी के अनुसार बोर्ड ने मुख्य कार्यकारी कमेटी के सुधार प्रस्तावों को मान लिया है। साथ ही कहा कि प्रारुप में हुए बदलावों से खेल में रोमांच बढ़ेगा और प्रतिस्पर्धी ढांचा बेहतर होगा और खिलाड़ियों व प्रशंसकों दोनों को ही लाभ होगा। बोर्ड ने आईसीस पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए क्वालीफाइंग प्रारुप को भी मंजूरी दे दी है। इससे एसोसिएट सदस्य देशों के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का रास्ता खुलेगा। विश्वकप में अब 14 योग्य टीमें हिस्सा लेंगी, जो एक बदले हुए प्रारुप में फाइनल तक पहुँचने के लिए तीन चरणों वाली प्रतिस्पर्धा से गुजरेंगी। इस नए ढांचे को इवेंट के हर चरण में प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है, जिससे पहले मैच से लेकर फाइनल तक हर मुकाबला महत्वपूर्ण और रोमांचक बना रहेगा। इससे पहले और दूसरे राउंड के मैचों का महत्व और बढ़ जाएगा, जिसके बाद एक बेहद प्रतिस्पर्धी सुपर 7 चरण होगा। इस चरण में 7 क्वालिफाइंग टीमें सेमी-फाइनल में जगह बनाने के लिए राउंड-रॉबिन चरण से गुजरेंगी। ज्यादा महत्व और बेहतर प्रतिस्पर्धी तीव्रता से प्रशंसकों को रामांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। इससे उभरती हुई टीमों को भी क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर मुकाबला करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही टी20 विश्वकप में भी बदलाव आयेंगे। उभरती हुई टीमों के शानदार प्रदर्शन से उत्साहित होकर आईसीसी ने टूर्नामेंट के दूसरे चरण में खेलने वाली टीमों की संख्या 8 से बढ़ाकर 10 करना तय किया है। इससे सुपर 10 चरण में क्रिकेट के उभरते देशों की भागीदारी बढ़ेगी और मुकाबले का स्तर भी ऊंचा होगा। इसके अतिरिक्त, ढ्ढक्करु की तरह ही एलिमिनेटर मैच को शामिल किया गया है, जिसमें सुपर 10 चरण के ग्रुप में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए आमने-सामने होंगी।

संक्षिप्त समाचार

शूटिंग शौक के तौर पर शुरू की थी, मेरे सपने को पूरा करने के लिए पिता ने प्रॉपर्टी बेची-सोनम मस्कर

नई दिल्ली।

कोल्हापुर की सोनम उत्तम मस्कर ने शूटिंग को बस शौक के तौर पर शुरू किया था और अब वह जापान के आइची-नागोया में होने वाले 20वें एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी कर रही हैं। सोनम ने बताया कि उनके पिता ने उनके सपने को पूरा करने के लिए जरूरी सामान खरीदने की खातिर एक प्रॉपर्टी बेच दी थी। 23 साल की 10 मीटर एयर राइफल शूटर उस भारतीय टीम का हिस्सा होंगी जो जापान जाएगी, जहां एशियाई खेलों में शूटिंग इवेंट्स 17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आइची प्रीफेक्चुरल जनरल शूटिंग गैलरी में होंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का सफर सोनम के लिए आसान नहीं रहा। शूटिंग को करियर के रूप में अपनाने के दौरान उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रोफेशनल शूटिंग उपकरण काफी महंगे थे और कोविड-19 महामारी के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई थी। इसके बावजूद सोनम ने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ती रहीं। सोनम ने उस पल को याद करते हुए कहा, ÷एक समय ऐसा था जब हम आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहे थे, खासकर लॉकडाउन के दौरान। जब यह साफ हो गया कि शूटिंग में आगे बढ़ने के लिए मुझे अपने खुद के सामान की जरूरत है, तो मेरे पिता ने एक प्रॉपर्टी बेच दी ताकि हम उसे खरीद सकें। यह हमारे परिवार के लिए एक बड़ा फैसला था, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है।÷ सोनम का शूटिंग से पहला परिचय 2018 में मुंबई के तोलानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ाई के दौरान हुआ था और इस खेल में प्रोफेशनल करियर बनाना कभी भी उनकी शुरुआती योजनाओं का हिस्सा नहीं था।

भूटिया और छेत्री ही नहीं भारतीय फुटबॉल में रहे हैं पीके बनर्जी, चुन्नी गोस्वामी जैसे सितारे

कोलकाता ।

भारतीय फुटबॉल की बात करें तो केवल दो खिलाड़ी ही लोकप्रियता हासिल करते हुए देश भर में अपनी पहचान बना पाये हैं। इनमें एक है सुनील छेत्री और दूसरे हैं बाईचुंग भूटिया। छेत्री और भूटिया ने आधुनिक भारतीय फुटबॉल को नई पहचान दी है। छेत्री ने अपने करियर में 95 से अधिक अंतरराष्ट्रीय गोल किए हैं और उन्हें भारतीय फुटबॉल का चेहरा माना जाता है, जबकि भूटिया ने 1990 के दशक में देश में फुटबॉल की लोकप्रियता बढ़ाई हालांकि भारतीय फुटबॉल इतिहास में कई अन्य दिग्गज खिलाड़ी भी रहे हैं। इसमें से एक को तो स्वयं विश्व फुटबॉल की शीर्ष संस्था फीफा ने 20वीं सदी का भारत का सबसे महान फुटबॉलर घोषित किया था। इस फुटबॉलर का नाम है। प्रदीप कुमार बनर्जी जो पी के बनर्जी के नाम से जाने जाते हैं। पी के बनर्जी की बदौलत ही भारतीय टीम ने 1962 के एशियाई खेलों में फुटबॉल का स्वर्ण पदक जीता था। पी के बनर्जी -पी के ने 1950 और 1960 के दशक में भारतीय टीम को एशिया में शीर्ष पर पहुँचाया। उन्होंने भारत के लिए 45 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 14 गोल किए। उनकी कप्तानी में भारत ने 1962 के जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। यह वह दौर था जब भारत ने फीफा विश्व कप के लिए पहली और आखिरी बार क्वालीफाई किया था, हालाँकि टीम खेलने ब्राजील नहीं गई।

मेसी ने बनाया महारिकार्ड

अटलांटा ।

अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने अपने जादुई प्रदर्शन से टीम को फीफा विश्वकप फाइनल में पहुंचाने के दौरान ही एक नया विश्व रिकार्ड भी अपने नाम किया है। इंग्लैंड के खिलाफ हुए रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में मेसी ने दो गोल करने में असिस्ट (सहायता) की इससे उनकी टीम को 2-1 से जीत मिली। इसके साथ ही मेसी के नाम अब विश्वकप में कुल 12 असिस्ट दर्ज हो गए हैं। इन 12 में से 10 असिस्ट उन्होंने टूर्नामेंट के बेहद दबाव भरे नॉकआउट मुकाबलों में किए हैं, जो उनकी असाधारण खेल समझ और दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता को दिखाते हैं। आंकड़ों के अनुसार मेसी इस अभूतपूर्व मुकाम तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। गौरतलब है कि विश्व कप के पूरे इतिहास में किसी अन्य खिलाड़ी ने 8 से अधिक असिस्ट नहीं किए हैं, जो मेसी की उपलब्धि को और भी खास बना देता है।

मैच के पहले हाफ में दोनों टीमों ने गोल के कई प्रयास किए लेकिन कोई भी टीम सफलता हासिल नहीं कर पाई। वहीं दूसरे हाफ की शुरुआत में इंग्लैंड ने 55वें मिनट में एंथनी गॉर्डन के गोल से1-0 की बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद अर्जेंटीना की ओर से लगातार प्रयास जारी रहे, और मुकाबले के आखिरी 7 मिनटों में टीम ने एक जबरदस्त वापसी करते हुए मैच का रुख ही पलट दिया। मैच के 85वें मिनट में मेसी के एक

बेहतरीन पास पर एंजो फर्नांडेज ने एक गोल दाग दिया। जिससे स्कोर 1-1 से बराबरी पर आ गया। इसके बाद मेसी ने फिर असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए एक शानदार पास दिया, जिसे लाउतारो मार्टिनेज ने हेडर की मदद से गोल में बदलने में कोई गलती नहीं करते हुए अर्जेंटीना को मैच में 2-1 से आगे कर दिया।

इंग्लैंड की हार से निराशा में डूबे कप्तान हैरी केन

जीत की दहलीज पर आकर भी उसे हासिल नहीं कर पाये

अटलांटा ।

इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने अर्जेंटीना के खिलाफ फीफा विश्वकप फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले में मिली 1-2 की हार पर निराशा जताते हुए कहा कि हम जीत की दहलीज पर पहुंचकर भी उसे हासिल नहीं कर सके। इससे टीम का खिताबी जीत का सपना भी टूट गया। उन्होंने कहा कि उनकी टीम जीत के बेहद करीब पहुंच चुकी थी पर निर्णायक क्षणों में वह लय बरकरार नहीं रख पायी जिसके कारण उसे बाहर होना पड़ा है।इस हार के साथ ही इंग्लैंड की टीम को साल 1966 के बाद से सेमीफाइनल में तीसरी बार हार का सामना करना पड़ा है। इससे पहले साल 1990 और 2018 में भी टीम सेमीफाइनल में ही बाहर हो गयी थी। इस बार इंग्लैंड ने दूसरे हाफ की शुरुआत में ही एंथनी गॉर्डन के शानदार गोल से 1-0 की बढ़त हासिल कर ली थी पर कप्तानी लियोनल मेसी के जादुई खेल से अर्जेंटीना ने मैच के अंतिम क्षणों में जबरदस्त वापसी करते हुए केवल सात मिनट में ही दो गोल दागकर मुकाबला जीत लिया। मेसी की सहायता से एंजो फर्नांडीज और लाउतारो मार्टिनेज ने गोल दागकर अपनी टीम को 2-1 से जीत दिलायी। मार्टिनेज का विजयी गोल इंजरी टाइम में आया, जिसने मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह मिली, वहीं इंग्लैंड के प्रशंसक निराशा में डूब गये। वहीं मैच के बाद केन ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा, मैं बहुत दुखी हूं। साथी खिलाड़ियों के लिए दुखी हूं, सभी के लिए दुखी हूं। उन्होंने आगे कहा, इस टूर्नामेंट में हमारे कई अच्छे पल रहे। हमने कई अच्छे मैच खेले और एक और सेमीफाइनल तक पहुंचे। हम हमेशा कहते हैं कि हम जीत के दरवाजे पर हैं, हम बहुत करीब हैं। हमें बस टूर्नामेंट के आखिरी चरण में उस गायब कड़ी को खोजने की जरूरत है। केन ने यह भी बताया कि ऐसे टूर्नामेंट कितने थका देने वाले होते हैं, जिनमें बहुत मेहनत, दबाव और मानसिक मजबूती की जरूरत होती है। अपनी टीम के प्रदर्शन का विश्लेषण करते हुए, केन ने स्वीकार किया कि 1-0 की बढ़त लेने के बाद उनकी टीम की रणनीति में खामी थी।

पूरन ने अमेरिकी मेजर लीग में 30 गेंदों पर शतक लगाया

न्यूयार्क । अमेरिकी मेजर लीग (एमएलसी) क्रिकेट टूर्नामेंट में एमआई न्यूयॉर्क की ओर से खेलते हुए वेस्टइंडीज के आक्राम बल्लेबाज निकोलस पूरन ने पहले एलिमिनेटर मुकाबले में 31 गेंदों में शतक लगाकर एक नया रिकार्ड अपने नाम किया है। यह एमएलसी में बनाया गया अब तक का सबसे तेज शतक है। पूरन ने 33 गेंदों की पारी में कुल 106 रन बनाए, जिसमें 13 छक्के और 5 शानदार चौके शामिल थे। पूरन ने पिच पर आते ही उन्होंने गेंदबाजों पर प्रहार शुरु कर दिये। इसके साथ ही पांच गेंदों में लगातार पांच लगा दिये। इस असाधारण पारी के साथ ही पूरन वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल के टी-20 क्रिकेट के सबसे तेज शतक 30 गेंद का रिकार्ड तोड़ने से एक गेंद से ही चूक गये। पूरन के इस आक्रामक पारी से एमआई न्यूयॉर्क ने निर्धारित 20 ओवरों में नौ विकेट पर 266 रन बनाये। यह किसी भी टी-20 लीग के एलिमिनेटर मुकाबले में बनाए गए सबसे बड़े स्कोरों में से एक है।

फीफा विश्व कप अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई

अटलांटा ।

अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया है। कप्तान लियोनेल मेसी का जादू आज फिर चला जिससे रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना की टीम ने बाजी मार ली। अब अर्जेंटीना की टीम लगातार दूसरे बार विश्वकप जीतने के लिए स्पेन का मुकाबला करेगी। इसमें उसका खिताबी मुकाबला 19 जुलाई को न्यूजर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में स्पेन से होगा। वहीं पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया था। अब शनिवार को तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अटलांटा स्टेडियम में अर्जेंटीना ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाते हुए इंग्लैंड पर दबाव बनाने का प्रयास किया। गेंद पर नियंत्रण और गोल करने के अवसरों को लेकर दोनों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा रही। वहीं इंग्लैंड ने भी अर्जेंटीना पर कई हमले किये। दोनों टीमों की रक्षापंक्ति ने पहले हाफ में जबरदस्त खेल दिखाया जिससे एक भी गोल नहीं हो पाया। वहीं दूसरे हाफ की शुरुआत से ही इंग्लैंड ने हमले शुरु कर दिए। मैच के 55वें मिनट में मोर्गन रोजर्स के शानदार पास पर एंथनी गॉर्डन ने सीधे गेंद गेंद गोल पोस्ट में डाल दी। इससे इंग्लैंड को मुकाबले में 1-0 की बढ़त मिल गयी। इस गोल के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ गया और उन्होंने लगातार अर्जेंटीना पर दबाव बनाए

रखा। जिससे ऐसा लगने लगा था कि अर्जेंटीना के लिए वापसी करना कठिन होगा।वहीं एक गोल से पिछड़ने के बाद गत चैम्पियन अर्जेंटीना ने कप्तान मेसी की सहायता से एक गोल कर स्कोर बराबरी पर ला दिया।

मैच के 85वें मिनट में मेसी के एक बेहतरीन पासपर एंजो फर्नांडेज ने गेंद गोल में डालने में कोई गलती नहीं की और स्कोर को 1-1 से बराबरी पर ला दिया। इसके बाद इंजरी टाइम में अर्जेंटीना ने तेजी से हमले शुरु कर दिये मेसी ने एक बार फिर अपनी महानता दिखाते हुए एक बेहतरीन पास दिया।

स्टोक्स अब कलब क्रिकेट खेलते हुए दिखेंगे

लंदन ।

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने कहा है कि वह क्लब क्रिकेट खेलते रहेंगे। ऐसे में अब स्टोक्स का अपने बचपन के क्लब डरहम के लिए खेलना तय है। स्टोक्स के अनुसार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बाद वह आराम का अनुभव कर रहे हैं। स्टोक्स ने कहा कि व सफेद-गेंद प्रारूप में फ्रैंचाइजी की ओर से खेलने पर भी विचार करेंगे। उन्होंने डरहम के हेड कोच रयान कैंपबेल को एक संदेश भी भेजा जिससे साफ है कि वह अभी भी खेल को लेकर उत्साहित हैं। स्टोक्स ने कहा, इस सप्ताह कुछ पल ऐसे भी आए जो सच में बहुत कठिन थे और इन सब चीजों ने यह साफ कर दिया कि मैंने सही फैसला लिया है। वहीं डरहम के हेड कोच कैंपबेल को पूरी उम्मीद है कि स्टोक्स इस गर्मी में वन-डे कप में खेलते दिखेंगे। यह टूर्नामेंट 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसमें डरहम का मुकाबला पहले राउंड में डर्बीशायर से होगा। स्टोक्स का द हंड्रेड टूर्नामेंट में खेलने के लिए कोई अनुबंध नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस सत्र की नीलामी में शामिल नहीं होने का फैसला किया था। द हंड्रेड टूर्नामेंट भी उसी दिन शुरू हो रहा है, इसलिए जो खिलाड़ी उस टूर्नामेंट के लिए चुने गए हैं, वे अपनी काउंटी टीमों के लिए वन-डे कप में नहीं खेल पाएंगे, जब तक कि उनकी फ्रेंचाइजी उन्हें खेलने की अनुमति न दे दे। स्टोक्स के इस फैसले से इंग्लैंड क्रिकेट में एक युग का अंत हो गया है, लेकिन उनके प्रशंसकों को क्लब स्तर पर अब उन्हें खेलते हुए देखने का अवसर मिलेगा।

संक्षिप्त समाचार

ईयू माइग्रेशन कानून पर विवाद: स्वीडिश सांसद ने डेनिश सांसद के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

स्टॉकहोम, एजेंसी। यूरोपीय संसद में हाल ही में पारित सख्त माइग्रेशन कानून को लेकर शुरू हुआ राजनीतिक विवाद अब कानूनी लड़ाई में बदल गया है। स्वीडन की सांसद आबिर अल-सहलानी ने डेनमार्क के सांसद क्रिस्टोफर स्टॉर्म के खिलाफ कथित नस्लीय टिप्पणी को लेकर स्वीडिश पुलिस में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने इस मामले की शिकायत यूरोपीय संसद की अध्यक्ष रोबर्टा मेट्सोला से भी की है। यह विवाद पिछले महीने यूरोपीय संसद द्वारा पारित रिटर्न रेगुलेशन के बाद शुरू हुआ। नए कानून के तहत यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को अवैध प्रवासियों के निर्वासन की प्रक्रिया तेज करने के लिए यूरोपीय संघ के बाहर 'रिटर्न हब' स्थापित करने की अनुमति दी गई है। कानून पारित होने के बाद संसद में 'उन्हें वापस भेजो' जैसे नारे लगे। इराकी मूल की स्वीडिश सांसद आबिर अल-सहलानी ने इन नारों की आलोचना करते हुए कहा कि यह कट्टर दक्षिणपंथी राजनीति का चिंताजनक उदाहरण है और इस घटना के बाद उन्होंने संसद में खुद को असुरक्षित महसूस किया। इसके जवाब में डेनिश सांसद क्रिस्टोफर स्टॉर्म ने सोशल मीडिया पर 'गो होम' टिप्पणी की। अल-सहलानी ने इसे नस्लीय घृणा फैलाने वाली टिप्पणी बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

चीन में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई: पूर्व पोलित ब्यूरो सदस्य मा शिंगरुई पार्टी से निष्कासित

बीजिंग, एजेंसी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व पोलित ब्यूरो सदस्य मा शिंगरुई को कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, मा पर भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और रिश्तेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप लगे हैं। मा शिंगरुई को अप्रैल में 'कानून और पार्टी अनुशासन के गंभीर उल्लंघन' के आरोप में जांच के दायरे में लिया गया था। जांच में पाया गया कि उन्होंने अधिकारियों की नियुक्ति और पदोन्नति में दूसरों को अनुचित लाभ पहुंचाया, अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया तथा रिश्तेदारों को बाजार मूल्य से कम कीमत पर संपत्ति खरीदने में मदद की। शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, मा ने महंगे उपहार स्वीकार किए और अपने परिवार के सदस्यों को सरकारी प्रभाव का इस्तेमाल कर बड़े आर्थिक लाभ दिलाए। जांच एजेंसियों ने इसे बड़े पैमाने पर 'पारिवारिक भ्रष्टाचार' (फैमिली करप्शन) बताया है। मा शिंगरुई पहले चीन के एयरोस्पेस उद्योग में वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं और उन्होंने देश के कई महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रमों की जिम्मेदारी संभाली थी।

पोलैंड की नेता ने 'हिटलर' जेलेंस्की की तस्वीर कूड़ेदान में फेंकी

वारसॉ, एजेंसी। पोलैंड की राजनेता और क्राकोव की मेयर पद की उम्मीदवार मरिआना श्राइबर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की तस्वीर कूड़ेदान में फेंक दी। उन्होंने यूक्रेन पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलिश नागरिकों के नरसंहार से जुड़े विवादित राष्ट्रवादी संगठनों और नेताओं का महिमामंडन करने का आरोप लगाया। वीडियो में श्राइबर ने जेलेंस्की की एक तस्वीर दिखाई, जिस पर हिटलर जैसी मूंछ बनाई गई थी। इसके बाद उन्होंने तस्वीर को मोड़कर कूड़ेदान में फेंकते हुए कहा कि 'अपराधियों का महिमामंडन करने वालों की जगह इतिहास के कूड़ेदान में है।' साथ ही आरोप लगाया कि यूक्रेन ने अब तक पोलिश नागरिकों के नरसंहार के लिए औपचारिक माफी नहीं मांगी है। श्राइबर ने यह टिप्पणी 11 जुलाई 1943 की 'ब्लडी संडे' घटना की बरसी पर की। उस दिन यूक्रेनी विद्रोही सेना ने वोल्हीनिया क्षेत्र के पोलिश गांवों पर एक साथ हमले किए थे।

'शेख हसीना लौटें, कानून का सामना करें': बांग्लादेश सरकार बोली- वापसी का स्वागत

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संभावित देश वापसी का स्वागत करते हुए कहा है कि उन्हें अदालत का सामना करना होगा। सरकार का कहना है कि उनके खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और अदालत का फैसला कानून के अनुसार लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री के सूचना एवं रणनीति सलाहकार जाहेद उर रहमान ने मंगलवार को मीडिया से कहा कि सरकार चाहती है कि शेख हसीना देश लौटें ताकि न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो सके। 78 वर्षीय शेख हसीना अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के दौरान सत्ता से बेदखल होने के बाद भारत आ गई थीं और तब से यहीं रह रही हैं। नवंबर 2024 में ढाका के विशेष न्यायाधिकरण ने छात्र आंदोलन पर कथित दमन और 'मानवता के खिलाफ अपराध' के मामले में उन्हें अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई थी।

भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन पहली बार अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे, 8 महीने के मिशन पर गए हैं आईएसएस

वॉशिंगटन, एजेंसी। भारतीय मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आठ महीने के अपने पहले अंतरिक्ष मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पहुंच गए हैं। वे रूस के सोयुज एमएस-29 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरने के बाद सुरक्षित रूप से आईएसएस पहुंचे, जहां वे वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी संबंधी प्रयोगों में हिस्सा लेंगे। कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपण के बाद करीब तीन घंटे और दो ऑर्बिट की यात्रा पूरी कर सोयुज एमएस-29 अंतरिक्ष यान दोपहर 1:52 बजे (ईडीटी) आईएसएस के प्रिचल मॉड्यूल से जुड़ा। मेनन के साथ रोस्कोस्मोस के कॉस्मोनॉट प्योत्र डुब्रोव और अन्ना किकिना भी ऑर्बिटल प्रयोगशाला पहुंचे। इससे पहले तीनों अंतरिक्ष यात्री सुबह 10:47 बजे (ईडीटी) यानी स्थानीय समयानुसार शाम 7:47 बजे बैकोनूर से रवाना हुए थे। उनके आईएसएस पहुंचने के बाद अगले लगभग दो सप्ताह के लिए स्टेशन पर क्रू सदस्यों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है।

लॉन्च से पहले, मेनन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया था, 'यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स की सेवा करने और नासा तथा हमारे अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के समर्थन में आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरने पर गर्व है! उन्होंने एक और पोस्ट में लिखा, 'कजाकिस्तान से सोयुज एमएस-29 पर लॉन्च होने और नासा तथा एक्सपेडिशन 74/75 के समर्थन में आठ महीने के मिशन की शुरुआत करने को लेकर उत्साहित हूं। नासा कम्युनिटी, दोस्तों, परिवार और प्रियजनों का आभारी हूं और कल के लिए उत्साहित हू। नासा के एस्ट्रोनॉट जेसिका मीर, जैक हैथवे और क्रिस विलियम्स; यूरोपियन स्पेस एजेंसी की एस्ट्रोनॉट सोफी एडेनोट; और रोस्कोस्मोस के कॉस्मोनॉट सर्गेई कुड-स्वेरचकोव, सर्गेई मिकाएव और आंद्रे फेड्याएव ने नए लोगों का स्वागत किया। इस मिशन को लेकर नासा की ओर से कहा गया कि मेनन, डुब्रोव और किकिना अप्रैल 2027 तक ऑर्बिटल लेबोरेटरी में रहेंगे। यह मेनन की अंतरिक्ष की पहली यात्रा है और डुब्रोव तथा किकिना दोनों के लिए यह दूसरा मिशन है। मिशन के दौरान मेनन वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन से जुड़े कई प्रयोग करेंगे, जिनका उद्देश्य मानव अंतरिक्ष अन्वेषण को आगे बढ़ाना और पृथ्वी पर जीवन को लाभ पहुंचाना है। वे अंतरिक्ष में सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के उत्पादन को बेहतर बनाने संबंधी शोध करेंगे, जिससे हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम और बेहतर मेडिकल डिवाइस के लिए जरूरी कंपोनेंट्स का बड़े पैमाने पर निर्माण किया जा सकती है। मेनन ऑगमेंटेड रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरीकों का इस्तेमाल करके अल्ट्रासाउंड भी करेंगे, जिससे भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों में पृथ्वी से मेडिकल सपोर्ट की जरूरत खत्म हो सकती है। नासा ने कहा कि मेनन उन स्टडीज में टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर भी काम करेंगे जिनमें यह देखा जाएगा कि अंतरिक्ष में ब्लड फ्लो कैसे बदलता है। साथ ही, वे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने और इलाज के नए तरीकों को विकसित करने के लिए माइक्रोग्रैविटी में बायोप्रिंटिंग वैस्कुलर कंस्ट्रक्ट्स का टेस्ट भी करेंगे।

नासा ने बताया कि ऑर्बिटल आउटपोस्ट पर अपना आठ महीने का साइंस मिशन पूरा करने के बाद विलियम्स, कुड-स्वेरचकोव और मिकाएव के जाने के बाद, 26 जुलाई को 'एक्सपीडिशन 75' शुरू होगा। 25 जुलाई को कमांड सौंपने का समारोह होगा, जिसमें स्टेशन की कमांड कुड-स्वेरचकोव से जेसिका मीर को सौंपी जाएगी। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से लगातार मानव उपस्थिति बनी हुई है। माइक्रोग्रैविटी के कारण यह वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक अनूठी प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है, जहां ऐसे कई प्रयोग संभव हैं जिन्हें पृथ्वी पर करना कठिन या असंभव है। यहां होने वाले अनुसंधान से चिकित्सा, इंजीनियरिंग, जीवविज्ञान और पदार्थ विज्ञान जैसे क्षेत्रों में प्रगति होती है तथा चंद्रमा और मंगल पर भविष्य के मानव मिशनों की तैयारी में भी मदद मिलती है।

पुल, पावर प्लांट सब तबाह कर देंगे, डोनाल्ड ट्रंप की खुली चेतावनी, फिर मच सकता है हाहाकार

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका और ईरान के बीच हुआ सीजफायर अब पूरी तरह टूट चुका है। दोनों देशों ने एक-दूसरे पर समझौता तोड़ने के आरोप लगाए हैं और भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। इस बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान जल्द से जल्द बातचीत की मेज पर नहीं लौटता, तो अगले हफ्ते से अमेरिकी सेना ईरान के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह तबाह कर देगी। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरानियों के पास डील करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है।

ट्रंप ने ईरान संग तनाव बढ़ने के बाद फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा, 'अगला हफ्ता उनके लिए बहुत बुरा होने वाला है क्योंकि अगले हफ्ते पावर प्लांट्स का नंबर आएगा। अगले हफ्ते पुलों की बारी आएगी। हम उनके सभी पावर प्लांट्स और सभी पुलों को उड़ा देंगे, जब तक कि वे समझौता नहीं कर लेते।' वहीं जब राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया कि अमेरिकी सेना का यह अभियान कब तक जारी रहेगा, तो उन्होंने तल्ख अंदाज में कहा, 'ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक मैं यह न कह दूं कि अब बहुत हो गया।' ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के पास समझौता करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है।

तैनात किए 20 से ज्यादा युद्धपोत तैनात : ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी सेना लगातार चौथे दिन ईरान के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया है कि ईरान के सभी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में नाकेबंदी को दोबारा पूरी तरह लागू कर दिया गया है। अमेरिकी सेना ने 20 से अधिक युद्धपोत और सैकड़ों लड़ाकू विमान भी तैनात कर दिए हैं। इस बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक बार फिर जंग का अखाड़ा बन गया है। अमेरिका के ऐक्शन पर ईरान ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। ईरान के उप-विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका ने इस्लामाबाद समझौता तोड़ दिया है। गरीबाबादी ने कहा, 'अमेरिका ने फिर से नाकेबंदी लागू करके और शर्तों से पीछे हटकर इस्लामाबाद समझौते को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है।' ईरान का साफ कहना है कि अमेरिका की इस आर्थिक और सैन्य नाकेबंदी के दबाव में वे किसी भी तरह की बातचीत की मेज पर वापस नहीं लौटेंगे। ऐसे में वैश्विक तेल और ऊर्जा बाजार पर एक बार फिर भारी संकट मंडराने लगा है। बता दें ईरान और अमेरिका के बीच बीते 28 फरवरी को भीषण जंग शुरू हो गई थी जिसमें हजारों लोग मारे गए। करीब 4 महीनों तक मची तबाही के बाद 17 जून को एक युद्धविराम समझौते पर सहमति बनी थी। इस समझौते के तहत 60 दिनों के लिए हमलों को रोकने पर सहमति बनी। वहीं परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर आगे की बातचीत शुरू की जानी थी। हालांकि अब बातचीत रद्द कर दी गई है।

ट्रंप का बड़ा बयान : रूस पर नए प्रतिबंधों में ईरान और हिज्बुल्लाह को भी किया जा सकता है शामिल

वॉशिंगटन, एजेंसी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम की ओर से समर्थित उस कानून में रूस पर लगाए जाने वाले कड़े प्रतिबंधों को बढ़ाकर ईरान और हिज्?बुल्लाह को भी शामिल किया जा सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि भारत और चीन जैसे देशों से जुड़े प्रस्तावों पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। व्हाइट हाउस में इराक के प्रधानमंत्री अली अल-जैदी के साथ बैठक के दौरान ट्रंप से पूछा गया कि क्या वह इस कानून पर हस्ताक्षर करेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि सांसद इस प्रतिबंध पैकेज का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह कदम ग्राहम के सम्मान में उठाया जा सकता है, क्योंकि वह रूस के खिलाफ कड़े कदमों के सबसे बड़े समर्थकों में से एक थे।

ट्रंप ने कहा, 'मुझे पता है कि लिंडसे इसे बहुत चाहते थे। ' उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि वे इसमें ईरान को भी जोड़ सकते हैं। वे ईरान को जोड़ेंगे, जो एक बहुत बड़ा कदम होगा। वे हिज्बुल्लाह को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि इस प्रस्ताव पर अभी बातचीत चल रही है, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए काफी समर्थन दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, लेन वे इसे गंभीरता से आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। यह लिंडसे के सम्मान में है, और यह उनका सबसे बड़ा मुद्दा था। वह इसे सी भी दूसरी चीज से ज्यादा चाहते थे। उन्होंने कहा, 'इस बात की अच्छी संभावना है यह हो जाएगा। जब उनसे पूछा गया क्या इस कानून में भारत और चीन जैसे देशों पर लगाए जाने वाले द्वितीयक प्रतिबंध भी शामिल होंगे, तो ट्रंप ने कहा अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा, 'अगर यह चीन, भारत और दूसरे देशों पर द्वितीयक प्रतिबंधों की बात है, तो हमें देखना होगा। इस पर अभी चर्चा नहीं हुई है।' यह बयान ट्रंप और इराकी प्रधानमंत्री के बीच इराक, ईरान और मध्य-पूर्व के मुद्दों पर हुई लंबी बातचीत के दौरान आया। ट्रंप ने एक बार फिर कहा क्षेत्र में ईरान का प्रभाव काफी कमजोर हो गया है। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है मध्य-पूर्व अब एक साथ आ रहा है।' ट्रंप ने कहा, 'हम मध्य-पूर्व के दबंग को हटा रहे हैं। ईरान मध्य-पूर्व का दबंग था। उसने इराक और हर दूसरे देश को डराया-धमकाया।' उन्होंने आगे कहा अब कोई डर नहीं है।

थाइलैंड में भारतीयों के लिए बिना वीजा के एंट्री जारी, लेकिन एक शर्त; पूरा मामला क्या

बैंकॉक, एजेंसी। थाइलैंड में भारतीय पासपोर्ट धारकों को बिना वीजा एंट्री मिलती रहेगी। हालांकि इसमें एक बदलाव भी किया गया है। बिना वीजा के भारतीय थाइलैंड में अधिकतम 30 दिन तक ही रुक पाएंगे। यह वजह, थाई सरकार ने एक खास वजह से लिया है। असल में भारतीयों के वीजा-फ्री एंट्री पर रोक लगाने संबंधी प्रस्ताव के बाद से भारतीय पर्यटकों की संख्या में काफी ज्यादा गिरावट आई थी। बता दें कि थाइलैंड के लिए भारत एक बड़ा मार्केट है। बड़ी संख्या में भारतीय थाइलैंड घूमने के लिए जाते हैं।

इसलिए लिया गया फैसला : थाइलैंड कैबिनेट ने मंगलवार को अपनी साप्ताहिक बैठक में भारतीय यात्रियों के लिए 30 दिन की वीजा-फ्री एंट्री को मंजूरी दे दी। पर्यटन मंत्री सुरसक पंचरोएनवोराकुल ने कहाकि इस कदम का उद्देश्य भारतीय पर्यटकों के लिए चीजों को आसान करना है।

इससे देश के पर्यटन उद्योग को भी सपोर्ट मिलेगा। उन्होंने कहाकि इसलिए कैबिनेट ने भारतीय पर्यटकों के लिहाज से 30 दिन की वीजा-फ्री एंट्री को मंजूरी दी। यह थाइलैंड के लिए एक बड़ा बाजार हैं। साथ ही पर्यटन मंत्री ने यह भी कहाकि अगर भविष्य में इस कदम से कोई समस्या आती है, तो सरकार इसकी समीक्षा कर सकती है।

पहले क्या था प्रावधान : भारतीय यात्रियों को फिलहाल बिना वीजा के थाइलैंड में 60 दिनों तक रहने की अनुमति है। लेकिन मई में थाई कैबिनेट द्वारा वीजा-मुक्त देशों की सूची को 93 से घटाकर 54 करने और 30 दिन की अवधि तय करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद यह पॉलिसी खत्म होने वाली थी। हालांकि, यह प्रस्ताव अभी तक लागू नहीं हुआ है। पर्यटन मंत्री के अनुसार, इस घोषणा ने भारतीय यात्रियों के बीच भ्रम पैदा कर दिया और यहां से थाइलैंड आने वालों की संख्या काफी कम हो गई। भारत इस साल चीन और मलेशिया के बाद थाईलैंड के लिए तीसरा सबसे बड़ा टूरिस्ट सोर्स है।

कुछ अन्य देशों को भी छूट : भारत के साथ-साथ, थाइलैंड ने क्रोएशिया, बुल्गारिया, साइप्रस, माल्टा और मालदीव के यात्रियों के लिए भी 30-दिन की वीजा-फ्री एंट्री को मंजूरी दी है। यह जानकारी डिप्टी सरकारी प्रवक्ता प्लॉयटाले लक्समीसांगचन ने दी। इस नए फैसले के बाद 30-दिन की वीजा-फ्री एंट्री के लिए योग्य देशों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। इसमें सभी 27 यूरोपीय संघ के सदस्य देश भी शामिल हैं।

क्यों बदल रहे वीजा पॉलिसी : वीजा नीति में बदलाव ऐसे समय में आ रहे हैं जब प्रधानमंत्री अनुतिन चर्णविराकुल की सरकार उन विदेशी देशों पर कड़ी निगरानी रखना चाहती है जिन पर थाइलैंड के वीजा-फ्री सिस्टम का गलत तरीके से इस्तेमाल करके गैरकानूनी गतिविधियां करने का आरोप है।

चुनाव से पहले सुलगा पीओके: मुजफ्फराबाद कूच से पहले पुलिस की गोली से नौ मरे, खूनी झड़प के बाद राजधानी की घेराबंदी

मुजफ्फराबाद , एजेंसी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओके) में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पाकिस्तान सरकार के खिलाफ चल रहा आंदोलन, जन आक्रोश में बदल गया है। ज्वॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) के बुधवार को प्रस्तावित मुजफ्फराबाद मार्च से पहले पूंछ डिवीजन में प्रदर्शनकारियों और पुलिस एवं पाकिस्तान रेंजर्स की रातभर हुई हिंसक झड़पों में नौ लोगों की मौत हो गई।

क्षेत्रीय तनाव बढ़ा : इस हिंसा में पाकिस्तान रेंजर्स के दो जवानों की भी मौत हुई है। घटना को लेकर प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के दावे अलग-अलग हैं, लेकिन पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर है। हजारों प्रदर्शनकारी आज रावलकोट, मीरपुर, कोटली, बाग और अन्य जिलों से मुजफ्फराबाद की ओर कूच करेंगे, जबकि पाकिस्तान प्रशासन ने राजधानी मुजफ्फराबाद में अभूतपूर्व सुरक्षा घेरा तैनात कर दिया है। पीओके के गृह सचिव चौधरी गुफ्तार हुसैन के हवाले से पाकिस्तानी अखबार डॉन ने खबर दी है कि प्रशासन किसी दबाव में नहीं आएगा और जेएएसी के आंदोलन को निर्ममता से कुचल दिया जाएगा।

पुलिस के अनुसार सुधनोती जिले के बलोच इलाके में सुरक्षाबलों के काफिले पर पहले प्रदर्शनकारियों ने फायरिंग की, जिसमें रेंजर्स के एक जवान की मौत हुई। वहीं जेएएसी समर्थकों का आरोप है कि गोलीबारी की शुरुआत सुरक्षाबलों ने की। सुरक्षा काफिला कोटली सरसावा से बलोच की ओर बढ़ रहा था, तभी सारन और बलोच गांवों के पास ग्रामीणों ने उसका रास्ता रोक दिया और इसके बाद हिंसक टकराव शुरू हो गया। मार्च से पहले पूरे क्षेत्र में आंदोलन तेज हो गया है। आठ जिलों में बड़े प्रदर्शन हो चुके हैं। रावलकोट के बाहरी इलाके में हजारों समर्थक कई दिनों से डेरा डाले हुए हैं। पूरा घटनाक्रम ऐसे समय हो रहा है जब 27 जुलाई को पीओके की 45 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान होना है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि चुनाव से ठीक पहले भड़का यह आंदोलन पाकिस्तान सरकार के लिए हाल के वर्षों की सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती बन गया है।

12 आरक्षित सीटों को लेकर भड़के लोग : जेएएसी की सबसे प्रमुख मांग विधानसभा में शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को समाप्त करने की है। संगठन का आरोप है कि इन सीटों के जरिये पाकिस्तान की मुख्यधारा की पार्टियां उन लोगों के वोट से मुजफ्फराबाद में सरकार बनवाती हैं जो पीओके में रहते ही नहीं हैं। जून में पीओके के सुप्रीम कोर्ट ने इन सीटों को सांविधानिक संरक्षण प्राप्त बताते हुए कहा था कि इन्हें केवल विधायी संशोधन के जरिये ही बदला जा सकता है। अदालत के इस फैसले के बाद आंदोलन और भड़क गया।

यूएन में भारत की दो-टूक: 80 साल पुरानी व्यवस्था बदलने की उठाई मांग, कहा- सुरक्षा परिषद में अब सुधार जरूरी

वाशिंगटन डीसी, एजेंसी। भारत ने मंगलवार (स्थानीय समय) को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में व्यापक सुधारों के लिए अपनी मांग दोहराई। इसके साथ ही बहुपक्षवाद को भविष्य के लिए उपयुक्त बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधार, महासभा को पुनर्जीवित करने और आर्थिक और सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) की भूमिका को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।

राजदूत हरीश परवथानेनी ने क्या कहा : भविष्य के लिए समझौते की समीक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र महासभा की अनौपचारिक बैठक के दौरान बहुपक्षवाद को भविष्य के अनुरूप बनाना' विषय पर आयोजित मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत हरीश परवथानेनी ने कहा, 'भारत के लिए, बहुपक्षवाद को भविष्य के अनुरूप बनाने की शुरुआत यह सुनिश्चित करने से होती है कि वैश्विक संस्थाएं समकालीन वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करें। उन्होंने आगे कहा कि यह सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार, महासभा के पुनरुद्धार और आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय तीनों आयामों में सतत विकास को आगे बढ़ाने में ईसीओएसओसी की मजबूत भूमिका की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।'

संघर्षों को लेकर क्या कहा : उन्होंने कहा, 'संयुक्त राष्ट्र के बारे में जनता की धारणा हाल के दिनों में प्रतिकूल रूप से बदल गई है, जिसका मुख्य कारण विश्व के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों में सुरक्षा परिषद की सार्थक हस्तक्षेप करने में असमर्थता है। सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी के बीच मानवीय पीड़ा को समाप्त करने में अप्रभावी रही है। इसलिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का मूल सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना सवालों के घेरे में आ गया है।'

परिषद की कमियां का क्या कारण : उन्होंने तर्क दिया कि परिषद की कमियां इसकी पुरानी संरचना के कारण हैं। उन्होंने कहा, 'सुरक्षा परिषद की कमियों का मूल कारण स्पष्ट है। 1940 के दशक के लिए बनाई गई अस्सी साल पुरानी संरचना समकालीन चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ है। एक संगठन के रूप में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार लाने में कोई खास प्रगति नहीं कर पाया है। अब तक की चर्चाएं आईएनजी ढांचे के तहत तैयार बयानों के अंतहीन चक्र तक ही सीमित रही हैं। कार्रवाई बिंदु 39 से 41 काफी हद तक कागजों पर ही रह गए हैं। यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है और इसमें बदलाव होना चाहिए। भविष्य के समझौते का जिक्र करते हुए भारतीय राजदूत ने कहा कि अंतर-सरकारी वार्ताओं (आईजीएन) के कार्य बिंदुओं का मसौदा समझौते के सह-सुविधाकर्ताओं के बजाय तत्कालीन आईजीएन सह-अध्यक्षों द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को उन प्रावधानों पर महत्वपूर्ण आपत्तियां हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि भारत रचनात्मक भावना से समझौते का समर्थन करता है।

ईरान के आईआरजीसी ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया

तेहरान, एजेंसी। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने मंगलवार को कहा कि उसने अपने 'ऑपरेशन नस्र 2' के तीसरे चरण के दौरान बहरीन और कुवैत में अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए. ये अटैक तेहरान पर हालिया अमेरिकी हमलों का बदला था. आईआरजीसी के एक बयान और ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के मुताबिक, इस ऑपरेशन में बहरीन और कुवैत में अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर एक साथ मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए. आईआरजीसी ने कहा कि उसकी नेवी और एयरोस्पेस फोर्सेज ने बहरीन में शेख ईसा एयर बेस पर कई हथियार और इक्विपमेंट स्टोरेज शेड, साथ ही अमेरिकी जहाजों और एयरक्राफ्ट के पार्ट्स को निशाना बनाया. इसमें आगे कहा गया कि ऑपरेशन ने कुवैत में अली अल सलेम एयर बेस पर एमक्यू-9 ड्रोन की तैनाती के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रैंप पर हमला किया, जिससे कई ड्रोन नष्ट हो गए. बयान में कहा गया, 'ऑपरेशन नस्र 2 की तीसरी लहर में आईआरजीसी नेवी और एयरोस्पेस फोर्सेज के बहादुर योद्धाओं ने कुछ घंटे पहले बहरीन में शेख ईसा बेस पर एक साथ मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन के दौरान दुश्मन के जहाजों और एयरक्राफ्ट के लिए कई हथियार और पार्ट्स स्टोरेज शेड को नष्ट कर दिया.' इसमें आगे कहा गया, 'उन्होंने कुवैत में अली सलेम बेस पर दुश्मन के एमक्यू-9 ड्रोन की तैनाती के रैंप पर भी हमला किया, जिससे कई ड्रोन नष्ट हो गए या उन्हें नुकसान पहुंचा.' बयान के मुताबिक ये हमले आईआरजीसी के बताए अनुसार दिन में पहले ईरान के कई तटीय मिलिट्री ठिकानों पर अमेरिकी मिलिट्री हमलों के जवाब में किए गए थे. बयान में कहा गया, 'जब तक अमेरिका के जुर्म जारी रहेंगे, हमलावरों पर जवाबी कार्रवाई और सजा जारी रहेगी, और अगर ये हमले दोबारा हुए, तो उन्हें हैरान करने वाले जवाब

मिलेंगे.' आईआरजीसी ने यह भी चेतावनी दी कि इस इलाके में अमेरिकी मिलिट्री कार्रवाई जारी रहने से एनर्जी एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा, यह दावा करते हुए कि 'जब तक इस इलाके में अमेरिका की बुराइयां मौजूद हैं, तब तक इस इलाके से तेल या गैस की एक भी बूंद एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी. साथ ही यह भी कहा कि ऐसी कार्रवाइयों से होर्मुज जलडमरूमध्य के खुलने में सिर्फ देरी होगी.' दिन में पहले अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि अमेरिकी सेना ने 13 जुलाई को रात 10:15 बजे ईस्टर्न टाइम पर ईरानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोऑर्डिनेटेड हमलों की एक और सीरीज पूरी कर ली है. मिलिट्री कमांड के मुताबिक पांच घंटे के ऑपरेशन में बुशहर, चाह बहार, जस्क, कोनारक, अबू मूसा और बंदर अब्बास में ईरान के दक्षिणी तट पर मौजूद खास ठिकानों को निशाना बनाया गया. सेंटकॉम ने कहा कि ईरानी कोस्टल डिफेंस सिस्टम, मिसाइल लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रोन पोजीशन और नौसैनिक क्षमताओं को बेअसर करने के लिए प्रिसिजन-गाइडेड हथियार तैनात किए गए थे. अमेरिकी मिशन का बताया गया मकसद होर्मुज से गुजरने वाले कमर्शियल शिपिंग लेन को खतरे में डालने की तेहरान की क्षमता को सिस्टमैटिक तरीके से कम करना है. ये दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री ट्रेड कॉरिडोर में से एक है. अमेरिकी मिलिट्री ने बताया कि मिडिल ईस्ट में 50,000 से ज़्यादा अमेरिकी सर्विस मेंबर अभी भी तैनात हैं. इससे इस बात पर जोर दिया गया कि सेना लड़ाई के लिए तैयार है. हाल की बातचीत से पता चलता है कि पश्चिम एशिया में लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो ईरान के अंदर टारगेटेड अमेरिकी हमलों से बढ़कर खाड़ी के पार मौजूद अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर सीधे जवाबी हमलों तक पहुँच गई है।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी, 149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

प्रसव के बाद किडनी फेलियर से जूझ रहीं महिलाओं ने मांगी इच्छामृत्यु

जयपुर (एजेंसी)। राजस्थान के कोटा शहर में पांच महिलाएं, जो प्रसव के बाद किडनी फेलियर से जूझ रही हैं, उन्होंने अब डायलिसिस कराने से इनकार कर दिया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से या तो किडनी ट्रांसप्लांट की व्यवस्था करने या इच्छामृत्यु की अनुमति देने का अनुरोध किया है। इन महिलाओं ने अपने परिजनों के साथ मिलकर जिला अधिकारियों को किडनी ट्रांसप्लांट सुनिश्चित करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद यह गंभीर कदम उठाया गया है। परिजनों का कहना है कि वे अपनी पत्नियों को इस तरह तड़पते हुए और नहीं देख सकते और अगर लिखित आश्वासन नहीं मिला तो वे उन्हें डायलिसिस के लिए लाना बंद कर देंगे। उनके अनुसार, ये महिलाएं चलती-फिरती लाशों की तरह जी रही हैं। मई की शुरुआत में बच्चे के जन्म के बाद से ही धन्नी सुमन, रागिनी मीणा, सुशीला महावर, पिंकी एयरवाल और आरती चौबदार नाम की इन महिलाओं की सेहत लगातार बिगड़ती गई है। वे 70 से अधिक दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं और इस दौरान उन्हें 32 बार डायलिसिस से गुजरना पड़ा है। सुमन के पति मोहन लाल ने बताया कि उनकी पत्नी को अब डायलिसिस शब्द से ही डर लगने लगा है। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया के एक घंटे के भीतर ही उन्हें उल्टी होने लगती है, वे बुरी तरह कांपने लगती हैं और तेज बुखार आ जाता है। इसी तरह, रागिनी ने भी डायलिसिस को बेहद दर्दनाक बताया और शिकायत की कि लंबे समय तक चले इलाज के बावजूद उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ है। पिंकी और आरती तो डायलिसिस से मना कर अस्पताल से बाहर भी चली गईं, अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए। रागिनी के पति लोकेश मीना ने यह भी दावा किया कि वार्ड स्टाफ उन पर रोज डिस्चार्ज लेने का दबाव डाल रहा है। न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल (एनएमसीएच) के अधिकारियों ने हालांकि इन आरोपों को खारिज किया है। एनएमसीएच के प्रिंसिपल डॉ. नीलेश जैन ने बताया कि सभी पांचों महिलाओं का इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें 20 दिन पहले ही डिस्चार्ज करने की मंजूरी मिल गई थी और वे डायलिसिस सेशन के लिए अस्पताल आ सकती हैं। डॉ. जैन ने यह चेतावनी भी दी कि डायलिसिस से इनकार करना जानलेवा हो सकता है।

विद्युत संकट गंभीर समस्या, सांसद सैलजा ने सीएम को पत्र लिख की समाधान की मांग

सिरसा (एजेंसी)। सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कालांवाली शहर और आसपास के इलाकों में लगातार बनी हुई विद्युत संकट की समस्या को गंभीर जनहित का विषय बताते हुए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा है। पत्र में कुमारी सैलजा ने कहा है कि चोरमार से कालांवाली आने वाली मुख्य विद्युत लाइन में बार-बार तकनीकी खराबियां आने से इलाके में बिजली आपूर्ति लगातार बाधित हो रही है। इससे आम नागरिकों, व्यापारियों, किसानों, विद्यार्थियों, स्वास्थ्य संस्थानों, लघु उद्योगों तथा अन्य जरुरी सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। भीषण गर्मी के मौसम में यह समस्या और ज्यादा गंभीर हो जाती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सैलजा ने सीएम सैनी से आग्रह किया है कि संबंधित विभाग को तत्काल निर्देश देकर मुख्य विद्युत लाइन का तकनीकी परीक्षण, आवश्यक उन्नयन, क्षमता वृद्धि, मरम्मत और आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए, ताकि कालांवाली एवं आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बार-बार होने वाली बिजली कटौती से स्थायी राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े इस विषय का शीघ्र समाधान किया जाना जरुरी है।

संजय राउत ने सीएम फडणवीस से रामरक्षा कार्यक्रम में आने का किया आग्रह

मुंबई (एजेंसी)। शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को 19 जुलाई को नागपुर में आयोजित हो रहे रामरक्षा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। शिवसेना यूबीटी नेता राउत ने उन्हें एक पत्र भी लिखा है और पोस्ट करते हुए कहा कि सीएम फडणवीस, रामरक्षा कार्यक्रम में शामिल होने जरूर आइए। हम सभी आपके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सदस्य ने पत्र में मुख्यमंत्री फडणवीस को प्रखर राष्ट्रभक्त और कट्टर हिंदुत्ववादी बताकर लिखा कि उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से यह कहा है कि वे भी अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। राउत ने कहा कि करोड़ों रामभक्तों की तरह फडणवीस की भी यह इच्छा थी कि अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बने और अब वह सपना साकार हो चुका है। पत्र में राउत ने आरोप लगाया कि कुछ लोग राम मंदिर को लेकर झूठा और भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। इसतरह के प्रचार से करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इस ध्यान में रखते हुए शिवसेना (यूबीटी) की ओर से रामरक्षा अभियान शुरू किया गया है। संजय राउत ने मुख्यमंत्री फडणवीस से आग्रह किया है कि वे 19 जुलाई, को शाम 4-30 बजे नागपुर के रामनगर स्थित राम मंदिर में आयोजित रामरक्षा कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल हों और वहां उपस्थित रामभक्तों का मार्गदर्शन करें। राउत के इस निमंत्रण को महाराष्ट्र की राजनीति में भी अहम माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने राजनीतिक मतभेदों से अलग हटकर मुख्यमंत्री फडणवीस को खुले तौर पर धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का न्यौता दिया है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि मुख्यमंत्री फडणवीस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं या नहीं।

दिल्ली में रफ्तार का कहर : डंपर ने महिला को कुचला, मौके पर मौत

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को बुद्ध विहार-कंझावला रोड पर तेज रफ्तार से आ रहे एक डंपर ने एक महिला को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त रोहिणी निवासी प्रियंका के रूप में हुई है। हादसे के बाद डंपर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस को शव निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। शव को सड़क से हटाने के बाद यातायात को सामान्य कराया गया। पुलिस ने हादसे में शामिल डंपर को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश जारी है। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह दर्दनाक हादसा दिल्ली में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और हिट-एंड-रन मामलों की गंभीर स्थिति को दिखाता है। एक दिन पहले ही सिंघु बॉर्डर के पास ड्यूटी पर तैनात दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से मौत हुई थी।

ममता से 30 साल पुरानी दोस्ती तोड़ कर किया आर-पार का ऐलान

राजनीति के 'गांधारी' और 'हिटलर' पर मदन मित्रा का तीखा वार

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया है। तीन दशकों तक ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में शामिल रहे कामारहाटी के विधायक मदन मित्रा ने अब पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी के साथ अपनी राजनीतिक दोस्ती को दरकिनार कर 'आर-पार' की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। मदन मित्रा का यह बागी तेवर राज्य की सियासत में नई बहस छेड़ चुका है।मदन मित्रा ने अपनी नाराजगी की मुख्य वजह पार्टी के भीतर का 'दमघोंटू' माहौल बताया है। उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले कुछ समय से पार्टी में उनका दम घुट रहा था और काम करने के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं थीं। ममता बनर्जी के आसपास का दायरा सिमटने की बात करते हुए उन्होंने बिना नाम लिए ममता को 'गांधारी' या 'धृतराष्ट्र' जैसी संज्ञा दी। मदन मित्रा का तंज साफ था कि नेतृत्व सब कुछ देखते हुए भी आंखें मूंदे बैठा है।

उन्होंने अभिषेक बनर्जी पर सीधा और सबसे तीखा हमला करते हुए उनकी तुलना 'हिटलर' से कर डाली। मदन मित्रा का आरोप है कि पार्टी में अब सिर्फ एक व्यक्ति की चलती है और जो उनके फैसलों पर सवाल उठाता है, उसकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे इस व्यवस्था से तंग आकर ही कालीघाट कैंप से दूरी बनाने पर मजबूर हुए हैं। हाल ही में चर्चा रही कि उन्होंने ममता बनर्जी से माफी मांगी है। इस पर स्पष्टीकरण देते हुए मदन मित्रा ने कहा कि उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए ममता को माफी का संदेश जरूर भेजा था क्योंकि वे आज भी उनका व्यक्तिगत सम्मान करते हैं। लेकिन उन्होंने साफ किया कि माफी मांगने का मतलब यह कतई नहीं है कि उनकी राजनीतिक परेशानियां खत्म हो गई हैं या वे पार्टी के तानाशाही रवैये से सहमत हैं। मदन मित्रा ने 21 जुलाई के कार्यक्रम और उसमें शामिल होने वाली भीड़ पर भी कटाक्ष किया। हाईकोर्ट के आदेश और भीड़ के दावों पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि अब राज्य की राजनीति का चेहरा बदलने का समय आ गया है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी अजेय नहीं है और यदि विपक्षी ताकतें एकजुट हो जाएं, तो आने वाले एक साल के भीतर पश्चिम बंगाल की राजनीति की दिशा पूरी तरह बदल जाएगी। उनके इस बगावती तेवर ने सत्ताधारी दल के अंदरूनी कलह को सार्वजनिक कर दिया है।

जगन्नाथ रथ यात्रा : शंकराचार्य निश्चलानंद से धर्मेंद्र प्रधान समेत कई नेताओं ने की मुलाकात

पुरी (एजेंसी)। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को जगन्नाथ रथ यात्रा के पावन अवसर पर श्री गोवर्धनमठ पुरीपीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज से मुलाकात की। प्रधान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- पावन रथ यात्रा के शुभ अवसर पर श्री गोवर्धनमठ पुरी पीठ के पूज्यपाद जगद्गुरु शंकराचार्य के श्रीचरणों में नमन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। उनका स्नेह और आध्यात्मिक मार्गदर्शन सदैव प्रेरणा देता है। सनातन परंपरा एवं श्री जगन्नाथ संस्कृति के इस महान आध्यात्मिक केंद्र में उपस्थित होकर मन श्रद्धा, शांति और आनंद से अभिभूत है। इससे पहले सीएम मोहन चरण माझी ने जगद्गुरु शंकराचार्य से मुलाकात की थी। उन्होंने आगे लिखा कि श्री गोवर्धन मठ में मुझे परम पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती महाराज की दिव्य उपस्थिति और उनके अमृतमयी आशीर्वाद को प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। उन्होंने लिखा कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, मानवीय मूल्यों की स्थापना और सामाजिक समरसता की रक्षा के लिए, परम पूज्य शंकराचार्य जी का अमूल्य जीवन-दर्शन और मार्गदर्शन सदैव एक प्रकाश-पुंज का कार्य करता है। जगद्गुरु की इस पावन उपस्थिति और मार्गदर्शन ने मुझे राज्य की जनता की निरंतर सेवा के लिए नई ऊर्जा और दृढ़ संकल्प से भर दिया है। पुरी से बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने भी शंकराचार्य से मुकालात की तस्वीरें साझा करते हुए एक्स पर लिखा- आज श्री जगन्नाथ धाम, पुरी में मुझे गोवर्धन मठ के परम पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वतीजी महाराज के दर्शन और पवित्र आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

पीएम मोदी आज आएंगे चंडीगढ़, ट्रैफिक पुलिस ने किया प्रमुख मार्गों को डायवर्ट

-लोगों को सलाह वैकल्पिक रास्तों का करें इस्तेमाल, साइकिल ट्रैक, फुटपाथ खड़े ना करें वाहन

चंडीगढ़ (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को चंडीगढ़ आ रहे हैं। उनके दौरे को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है ताकि लोगों को आने-जाने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। पुलिस के मुताबिक चंडीगढ़-नयागांव बैरियर से लेकर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज लाइट प्वाइंट और सेक्टर-2/3/10-11 चौक तक ट्रैफिक प्रभावित रह सकता है, जिसके चलते ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। वहीं लोगों को सलाह दी है कि दोपहर 3 बजे तक इस रूट का इस्तेमाल करने से बचें और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक रास्तों का सहारा लें।

इसके अलावा ट्रैफिक की ताजा जानकारी प्राप्त करने के लिए लोगों से चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नजर बनाए रखने की अपील की गई है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले मेहमानों, अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने वाहन केवल तय पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करें। साइकिल ट्रैक, फुटपाथ या नो-पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर वाहनों को टो भी किया जाएगा।

बताया जा रहा है कि पीएम मोदी शुक्रवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए राजेंद्र पार्क जाएंगे। इसके बाद वह सड़क मार्ग से पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचेंगे। सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने दो संभावित रूट तय किए हैं। पहले रूट के मुताबिक पीएम का काफिला राजेंद्र पार्क से रवाना होकर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री आवासों के बीच वाले मार्ग से विज्ञान पथ होते हुए सीधे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचेगा।

वहीं वैकल्पिक रूट के तहत काफिला राजेंद्र पार्क से निकलकर पंजाब के सीएम हाउस के सामने से गुजरते हुए नयागांव रोड के रास्ते पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज तक जाएगा। सुरक्षा कारणों से दोनों मार्गों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं और जरूरत पड़ने पर इनमें से किसी भी रूट का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक अन्य वैकल्पिक रूट एयरपोर्ट से तैयार किया गया है, जिसके तहत काफिला एयरोपोर्ट स्थित एयरफोर्स एंट्री से रवाना होकर एयरपोर्ट चौक, ट्रिब्यून चौक, मध्य मार्ग, ट्रांसपोर्ट चौक और पंजाब राज्यभवन वाले रास्ते से विज्ञान पथ के रास्ते होते हुए पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचेगा।

वांगचुक बोले-रिपोर्ट नॉर्मल है, इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं

संसद कूच की हुंकार : 19वें दिन भी डटे सोनम वांगचुक

नई दिल्ली(एजेंसी)। लद्दाख की संवैधानिक सुरक्षा और अन्य अधिकारों की मांग को लेकर देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहा आंदोलन अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। पिछले 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन का आज 19वां दिन है। बिगड़ती सेहत के बीच वांगचुक ने बुधवार देर रात सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर देश की जनता से आगामी 20 जुलाई को संसद मार्च में शामिल होने की एक बेहद भावुक और बड़ी अपील की है।

लगातार बढ़ते दबाव के बीच अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए सोनम वांगचुक ने कहा कि उन्हें देशभर से हजारों आम नागरिकों, समाज के बड़े-बुजुर्गों और विभिन्न राजनीतिक नेताओं के संदेश मिल रहे हैं कि वे अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दें। कुछ शुभचिंतकों ने तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है ताकि सरकार उन्हें जबरन खाना खिला सके। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा कि अगर वे आज खाना खा लेते हैं तो इससे सरकार को यही संदेश जाएगा कि जनता के प्रति जवाबदेही की कोई ज़रूरत नहीं है; लोग बैठते हैं और खुद ही उठकर चले जाते हैं। अपनी शारीरिक स्थिति पर चिंतित समर्थकों को ढाढस बंधाते हुए उन्होंने बताया कि 18 दिनों के अनशन के बावजूद उनके मेडिकल टेस्ट के रिज़ल्ट्स काफी नॉर्मल हैं। शरीर में कमजोरी जरूर बढ़ रही है और मांसपेशियां (मसल्स) खत्म हो रही हैं, लेकिन उनका दिल अभी भी ठीक से काम कर रहा है। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा कि वे अभी इतने कमजोर नहीं हुए हैं कि दो-चार दिन में हिम्मत हार जाएं, और वे इस अनशन को कई दिनों तक आगे खींच सकते हैं।

वांगचुक ने देश की जनता से आग्रह किया कि वे सिर्फ उनसे अनशन तोड़ने के लिए न कहें, बल्कि खुद भी लद्दाख के इस हक की लड़ाई में एक छोटा कदम उठाएं। आगामी 20 जुलाई से देश की संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसे देखते हुए जंतर-मंतर पर पहले से ही परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों के विरोध में और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर चलो संसद अभियान के तहत एक शांतिपूर्ण मार्च निकालने की तैयारी चल रही है। वांगचुक ने इस प्रदर्शन के साथ एकजुटता जताते हुए जनता से अपील की कि 20 जुलाई को सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आएं कि सरकार तक एक अटूट संदेश पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब हम हज़ारों की संख्या में मिलकर लद्दाख के इस पूरे मुद्दे को देश की संसद के हवाले कर देंगे, तब उन्हें भरोसा हो जाएगा कि यह लड़ाई अब सही हाथों में चली गई है।

लाल किला एक महीने के लिए आम जनता और सैलानियों के लिए बंद

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत की स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ समारोह की भव्य तैयारियों और सुरक्षा इंतजामों के मद्देनजर लाल किला परिसर को एक महीने के लिए आम जनता और सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को देखते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि लाल किला 15 जुलाई से 15 अगस्त 2026 तक स्वतंत्रता दिवस समारोह समाप्त होने तक आम जनता और पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एएसआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस से पहले हर साल इस तरह का आदेश जारी किया जाता है।

सीता के पति... पर विवादित टिप्पणी मामले में फंसे कुणाल कामरा

जंतर-मंतर पर की टिप्पणी पर भड़के लोग

नई दिल्ली (एजेंसी)। हास्य कलाकार कुणाल कामरा ने जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन के मंच से भगवान राम को लेकर एक बेहद विवादास्पद टिप्पणी कर दी, जिसके बाद उन्हें देश भर के लोगों की तीव्र आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में कामरा यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये जो सरकार है और ये जो कर रही है, बहुत सालों से कर रही है। हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। कामरा का यह बयान स्पष्ट रूप से नीता अंबानी के पति मुकेश अंबानी की ओर इशारा कर रहा था। विपक्षी नेता और मोदी सरकार के आलोचक अक्सर सरकार पर अंबानी जैसे उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते रहे हैं। कामरा ने भी इसी तरह की आलोचना की, लेकिन भगवान राम का नाम लेने की बजाय जिस तरीके से उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से मजाक किया और इस पर लोग हंसते हुए ताली बजाने लगे, उसको लेकर विशेष आपत्ति जाहिर की जा रही है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, बीजेपी वाले सीता के पति का नाम लेके काम करते हैं। यह आज सीजेपी के मंच से कुणाल कामरा ने बोला। सीजेपी के मंच से लगातार भगवान श्री राम का अपमान हो रहा है। कुछ दिन पहले जय श्री राम के नारे को लेकर भी आपत्तिजनक बातें हुई थीं। एक अन्य यूजर ने दिल्ली पुलिस से कामरा और दीपके के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए लिखा, आज अभिजीत दीपके ने कुणाल कामरा को सीजेपी प्रदर्शन पर बुलाया। जैसे ही उन्हें स्टेज मिला, कामरा ने अपना भाषण शुरू किया और हिंदू देवी-देवताओं का मजाक उड़ाते हुए बोला - सीता का पति। इस अश्लील मजाक पर अभिजीत दीपके ताली बजाते और हंसते नजर आए। करोड़ों हिंदू मां सीता की पूजा करते हैं। क्या ये लोग इस्लाम या ईसाई धर्म के पवित्र व्यक्तियों का भी ऐसे ही मजाक उड़ाने की हिम्मत करेंगे? यह घटना एक बार फिर धार्मिक भावनाओं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच की नाजुक रेखा पर बहस को तेज कर दिया है। इस बयान को लेकर कई लोग उन पर निशाना साध रहे हैं और दिल्ली पुलिस से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कामरा की इस टिप्पणी को हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया जा रहा है। उनके साथ मंच पर मौजूद अभिजीत दीपके भी इस टिप्पणी पर तालियां बजाते और हंसते हुए दिखे, जिसके लिए उन्हें भी सार्वजनिक रूप से खूब कोसा जा रहा है।

कम बारिश से कर्नाटक में सूखे की स्थिति, डिप्टी सीएम ने पीएम को लिखा पत्र

-राज्य को अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का किया अनुरोध

बेंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक में कमजोर मानसून के कारण सूखे की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। इस बीच राज्य के उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने एनडीआरएफ के नियमों में राहत देने और राज्य को अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पत्र में परमेश्वर ने कहा कि दक्षिण-पश्चिम मानसून में कर्नाटक में सामान्य से कम बारिश हुई है। इसका सीधा असर खेती, पेयजल व्यवस्था, भूजल स्तर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। बता दें जून महीने में कर्नाटक में 42 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई, जबकि कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में 36 फीसदी बारिश की कमी रही। जुलाई में भी स्थिति नहीं सुधरी और राज्य में अब तक 34 फीसदी कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं बेंगलुरु में भी सामान्य से करीब 34 फीसदी कम बारिश हुई।

उपमुख्यमंत्री परमेश्वर ने कहा कि आकलन के मुताबिक कम बारिश और अधिक तापमान के कारण प्रभावित इलाकों में करीब 80 फीसदी बोई गई फसल बर्बाद हो चुकी है। उन्होंने इसके लिए मुख्य रूप से अल नीनो के प्रभाव को जिम्मेदार बताया। साथ ही कहा कि कई जिलों में भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है, जिससे सिंचाई और पेयजल संकट और गहरा गया है। पत्र में बताया गया है कि विजयनगर (61 फीसदी), मैसूर (55 फीसदी), मडिकेरी (51 फीसदी), चिक्कमगलुरु (48 फीसदी), दावणगेरे (47 फीसदी), हावेरी (46 प्रतिशत, शिवमोग्गा (44 फीसदी), कलबुर्गी (43 फीसदी), मंगलुरु (43 फीसदी) और बीदर (40 फीसदी) जैसे जिलों में बारिश की भारी कमी दर्ज की गई है। परमेश्वर ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि कर्नाटक द्वारा सूखे का आधिकारिक ज्ञापन भेजने से पहले मौजूदा सूखा आकलन के नियमों की समीक्षा की जाए।

उन्होंने मांग की कि एफआरयूआईटीएस डेटाबेस को छोटे और सीमांत किसानों की पहचान के लिए स्वीकार किया जाए। वर्तमान में 2015-16 की कृषि जनगणना के आधार पर सहायता तय की जाती है, जो अब राज्य की वास्तविक कृषि स्थिति को नहीं दर्शाती। उन्होंने सूखा मैनुअल-2020 के प्रावधानों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के मानकों के अनुरूप बनाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि मौजूदा राहत दिशानिर्देशों के तहत 33 फीसदी से ज्यादा फसल नुकसान होने पर सहायता दी जाती है, जबकि सूखा मैनुअल में 50 फीसदी फसल नुकसान होने पर ही गंभीर सूखे की श्रेणी में माना जाता है।

इसके अलावा उन्होंने केंद्र से सूखे का आकलन करने में ज्यादा लचीलापन अपनाने, वैज्ञानिक आधार पर कम अवधि के सूखे को भी मान्यता देने और सूखे की जल्द घोषणा से जुड़े नियमों में बदलाव करने की मांग की, ताकि किसानों को समय पर राहत मिल सके। डिप्टी सीएम परमेश्वर ने केंद्र सरकार से अपील की कि मौजूदा हालात को राष्ट्रीय महत्व की आपदा घोषित करने या उसी स्तर की सहायता प्रदान करने पर विचार किया जाए।

नौवीं में तीसरी भाषा बच्चों पर बढ़ाती है दबाव: सुप्रीम कोर्ट की सलाह

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी कर कहा है कि नौवीं कक्षा में तीसरी भाषा को अनिवार्य नहीं करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने बच्चों पर बढ़ते शैक्षिक दबाव और तनाव को देखकर महत्वपूर्ण सलाह दी है। यह टिप्पणी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की तीन भाषा नीति के खिलाफ चल रहे विवाद के बीच आई है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग मामले की सुनवाई के दौरान कही।

सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई थी, इसमें तमिलनाडु सरकार को हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवीएस) स्थापित करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जब नवोदय विद्यालय की ओर से पेश वकील ने तीसरी भाषा के नौवीं कक्षा से अनिवार्य होने का जिक्र किया, तब जस्टिस नागरत्ना ने इस पर अपनी कड़ी आपत्ति जाहिर की है।

जस्टिस नागरत्ना ने कहा, यह बहुत गलत बात है। सीबीएसई में नौवीं कक्षा अपने आप में ही तनावपूर्ण होती है। आप नौवीं क्लास में तीसरी भाषा क्यों लाते हैं? आप इस छठी क्लास में ही शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि पांचवीं या छठी कक्षा में तीसरी भाषा शुरू कर देनी चाहिए और नौवीं कक्षा तक इसकी पढ़ाई खत्म होना चाहिए। उन्होंने अपने स्कूल के दिनों को याद कर बताया कि कैसे उनके समय में भी पढ़ाई का दबाव था, खासकर जब आईसीएसई और एसएसएलसी जैसे अलग-अलग पाठ्यक्रम साथ चलते थे। उन्होंने कहा, जब हमारे समय में ऐसी तैयारी थी, तब आज क्या स्थिति होगीज बच्चों पर कितना दबाव होता है, यह देखिए। उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया कि नौवीं क्लास में कोई नई भाषा न रखी जाए, क्योंकि आठवीं क्लास के आखिर से ही छात्रों पर पढ़ाई का दबाव शुरू होता है।

सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) पर भी बात की और स्पष्ट किया कि एनईपी में हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा नहीं कहा गया है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा, राज्य की भाषा सिखानी होगी। अंग्रेजी सिखानी होगी। और कोई तीसरी भाषा भी। जरूरी नहीं कि वह हिंदी ही हो। वह संस्कृत हो सकती है। कोई भी तीसरी भाषा। संस्कृत क्यों नहीं? आपको हिंदी नहीं चाहिए, तब क्या संस्कृत भी नहीं चाहिए?